● वर्ष-5
● अंक-215
रायपुर, शनिवार
25 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› वित्त मंत्री ने विकास कार्यों ...

विश्व के पहले 'भारतदुर्गा मंदिर' का हुआ शिलान्यास

शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है: भागवत

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विश्व के पहले 'भारतदुर्गा मंदिर' के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम डॉ. आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्थान के जमठा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां भूमि पूजन और शिलान्यास उनके हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर कई प्रमुख धर्माचार्य और संत मौजूद रहे, जिनमें गुरुशरणानंद महाराज, श्री जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, स्वामी मित्रानंद महाराज, साध्वी ऋंभरा देवी और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री प्रमुख रूप से शामिल थे।

मोहन भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा, राम मंदिर आंदोलन के निर्माण को लेकर 30 साल तक दुविधा बनी रही. मुझसे लोग पूछते थे कि कैसे होगा? तो मैं कहता था कि होगा, लेकिन कैसे होगा? वो मुझे पता नहीं. मैं कह देता था कि भाऊराव देवरस जी ने कहा है 20 या 30 साल में हो जाएगा. अगर नहीं हुआ तो

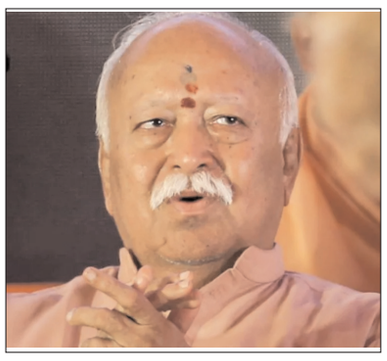

30 साल के बाद पूछना, उसके पहले मत पूछो. मैंने एक भरोसा मन में पैदा कर लिया था. और 2010 में 20 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया. इससे यह पता चलता है कि जो अनिवार्य है, वह होकर रहता है.

भारत की पूजा करनी है तो भारत बनना पड़ेगा

इस मौके पर अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा, भारत को भारत की पूजा करनी है तो भारत बनना पड़ेगा, भारत को जानना पड़ेगा, भारत को मानना पड़ेगा। अंग्रेजों की डेढ़ सौ साल की गुलामी के पश्चात हमारे मन और बुद्धि पर पश्चिमी लेप चढ़ गया है, उसको उतार कर वहां जाना पड़ेगा। शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है, सत्य को भी शक्ति का सहारा लेकर ही दुनिया में प्रचलित करना पड़ता है। एक भारतवर्ष ऐसा है जिसमें सत्य को सत्य के मूल में ग्रहण करते हैं, शक्ति की आवश्यकता रहती नहीं। बाकी दुनिया तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मानने वाली है।

दुनिया की हालत और भारत का रास्ता

सरसंघचालक ने वैश्विक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा, आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें भारत का विचार और रास्ता ही एकमात्र विकल्प है. अगर भारत का रास्ता दुनिया ने नहीं अपनाया तो भविष्य है क्या?

उन्होंने आगे कहा किक्या होगा और कैसे होगाकी दुविधा में न पड़ें. यानी जो अनिवार्य है उसके बारे में शंका मत रखना. हमें बस अपना कर्तव्य निभाते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ाना है.

आत्मविश्वास और पक्की अवस्था

संघ प्रमुख भागवत ने स्वीकार किया कि अभी हमारी अवस्था पक्की होनी बाकी है और प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य में भारत का उत्थान कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया को अब भारत की आवश्यकता है.

मंदिर ही नहीं, सबको करनी होगी पूजा

मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा, मंदिर हो गया, उसकी व्यवस्था भी बनेगी, यहां रोज पूजा-अर्चना होगी, विधिवत होगी। हम लोग भी आते रहेंगे। भारत दुर्गा की पूजा केवल मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक करेंगे, इससे नहीं होगा। वह पूजा हम सबको करनी पड़ेगी और उसकी पूजा की विधि अलग है। हमें निर्भय होना पड़ेगा। अभी देखेंगे तो पता नहीं चलता कि भारत विश्व गुरु होने वाला है। आज विचार कीजिए दुनिया की जो हालत है, उसमें अगर भारत का रास्ता दुनिया ने नहीं लिया तो भविष्य क्या है। संतों के मुख से जो घोषणा हुई है, भारत विश्व गुरु बनेगा।

भाजपा के हुए राघव

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर चल रहा सियासी संकट अब बड़े राजनीतिक भूचाल में बदल गया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को इस्तीफा देते हुए भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत कुल सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है।

राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से दो-तिहाई यानी सात सांसदों ने संविधान के प्रावधानों के तहत भाजपा में विलय का फैसला किया है। उनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी भी भाजपा में शामिल होंगे।

इस घटनाक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल 2026 को हुई थी, जब पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी थीं। राघव ने उस समय बयान दिया था कि मैं घायल हूं, इसलिए घातक हूं और मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक रहस्यमय बना दिया था। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व को राघव चड्ढा की सक्रियता में कमी और कुछ मुद्दों पर उनकी चुप्पी को लेकर आपत्ति थी। वहीं, चड्ढा समर्थक इसे अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व संकट का परिणाम बता रहे हैं। अशोक मित्तल का पार्टी छोड़ना भी चर्चा में है, क्योंकि उनके यहां हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई हुई थी।

रायपुर। डबल इंजन की हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गांवों के समग्र विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

विस्तृत समाचार पेज-8 पर

चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

- तीर्थयात्रियों में केदारनाथ धाम के लिए अधिक उत्साह
- केदारनाथ में तीन दिन में 93 हजार से अधिक दर्शनार्थी
- छह दिनों में चारधाम यात्रा में 1.82 लाख यात्री
- भीड़ प्रबंधन के बावजूद यात्रा सुचारु, उत्साह बरकरार

देहरादून। हिमालय की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। तीन दिन में ही केदारनाथ धाम पहुंचकर 93252 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।

केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन रिकार्ड 38 हजार यात्रियों ने दर्शन किए थे।

केदारनाथ में दर्शन को लंबी लाइन लग रही है। प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती है, लेकिन बेहतर व्यवस्थाओं के चलते यात्रा सुचारु रूप से संचालित हो रही है। छह दिनों में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1.82 लाख पार कर चुकी है।

19 अप्रैल से गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। 22 अप्रैल को केदार धाम के कपाट खुले थे।केदारनाथ धाम में पहले दिन 38 हजार, दूसरे दिन 25 हजार से अधिक और तीसरे दिन 30 से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। यहां आने वाले श्रद्धालु तीर्थाटन के साथ ही पर्यटन का भी आनंद ले रहे हैं।श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह है कि कठिन पैदल मार्ग और मौसम की चुनौतियों के बावजूद उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं।हर पड़ाव पर आस्था और संस्कृति की बहुरंगी झलक देखने को मिल रही है। गंगोत्री व यमुनोत्री में भी यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है।छह दिनों में दोनों धामों में 64 हजार से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बदरीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों में भी उत्साह है। गुरुवार से शुरू हुई यात्रा में पहले दिन 14 हजार से अधिक तो शुक्रवार को 10 हजार से अधिक यात्री दर्शन को पहुंचे।

पश्चिम बंगाल: शांतिपूर्ण चुनाव से सुप्रीम कोर्ट हुए प्रभावित

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर इस बार एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली हैं। जहां आमतौर पर चुनाव के दौरान तनाव और हिंसा की खबरें सामने आती हैं, वहीं इस बार मतदान प्रतिशत और शांति दोनों ने ध्यान खींचा हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में हुए भारी मतदान प्रतिशत और शांतिपूर्ण माहौल की सराहना की हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक नागरिक के रूप में उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में भाग लिया हैं। उनका मानना है कि जब लोग लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो हिंसा की संभावना काफी कम हो जाती हैं।गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने न्यायालय को बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में करीब 92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

प्रमुख समाचार

73 सांसदों ने पेश किया चुनाव आयुक्त को हटाने प्रस्ताव

नईदिल्ली। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर आचार संहिता लागू करने में प्रक्रियात्मक पक्षपात और प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर निष्क्रियता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस और टीएमसी समेत 73 सांसदों

द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में ष्टश्वष्ट के आचरण को संविधान पर हमला बताया गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रक्रियात्मक पक्षपात के आरोपों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ औपचारिक आरोपों में आचार संहिता के प्रवर्तन में निरंतर पक्षपातपूर्ण असमानता शामिल है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ शिकायतों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है।

बंगाल महफूज, मणिपुर पर क्यों चुप हैं पीएम मोदी: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुगली नदी में की गई बोट राइड को लेकर एक जोरदार तंज कसा है। ममता ने कहा है कि पीएम मोदी बंगाल की हुगली नदी में बोट की सवारी का आनंद इसलिए ले सके क्योंकि यहां का पानी बिल्कुल साफ है। उन्होंने दिल्ली

की यमुना नदी की खराब हालत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित है, जिसकी वजह से पीएम मोदी वहां ऐसी सवारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ममता ने यमुना की इस खराब हालत के लिए सीधे तौर पर वहां की भाजपा सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरी खबर को विस्तार से समझें तो हावड़ा में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह तीखा हमला बोला। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने हुगली नदी में नाव की सवारी करने का फैसला किया। ममता ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम जैसे निकायों ने नदी के किनारों को बहुत सुंदर और साफ-सुथरा बना दिया है।

मोदी जी की एसआईआर प्रक्रिया उन्हीं के खिलाफ : केजरीवाल

नई दिल्ली,। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में रिकॉर्ड मतदान के बाद मोदी जी की एसआईआर प्रक्रिया

उन्हीं के खिलाफ जा रही है। केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखा कि बंगाल में यह बात सामने आ रही है कि लोग एसआईआर के खिलाफ मजबूती से वोट डाल रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा यह घोषणा करने के कुछ ही समय बाद आई कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है, क्योंकि मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद से बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में प्रथम चरण में तमिलनाडु के 84.80 प्रतिशत की तुलना में 91.91 प्रतिशत का उल्लेखनीय रूप से उच्च मतदान दर्ज किया गया।

तलाक की कार्यवाही शुरू होती है, हर कोई बेरोजगार बन जाता है: सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक तलाक से जुड़ा मामला शुक्रवार को आया, जिसमें जज ने अहम टिप्पणी की। इस मामले में पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि उसे तलाक नहीं चाहिए। बाद में कोर्ट

ने पति को 50 लाख रुपए की एलिमनी देने का आदेश दिया। पति का कहना था कि उसकी पत्नी ने इतना एलिमनी तो मांगा भी नहीं है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पति पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे ही तलाक की कार्यवाही शुरू होती है, हर कोई बेरोजगार बन जाता है।बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तलाक से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी। इस पर पति ने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि तलाक के लिए अर्जी पत्नी ने दी है? किस आधार पर दी है, जिस पर पति ने जवाब दिया कि क्रूरता और परित्याग के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार का झूठा आरोप, जिसे आप साबित नहीं कर पाए, यही अपने आप में तलाक का एक आधार है।

अब व्हाट्सएप पर मिलेगी जनगणना की हर जानकारी

नई दिल्ली। भारत में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है। लोगों की सुविधा और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने एक नई सेवा शुरू की है। अब जनगणना से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब पाना बहुत आसान हो गया है। सरकार ने इसके लिए एक खास राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी कर दिया है। इसके साथ ही, आज के डिजिटल समय को देखते हुए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है ताकि लोग आसानी से अपने मोबाइल पर जानकारी हासिल कर सकें। इस नई सुविधा का सीधा मकसद जनगणना के पहले चरण को आसान बनाना है। नई दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक, यह नया हेल्पलाइन नंबर 1855 मुख्य रूप से आवास सूचीकरण और आवास गणना से जुड़े सवालों का तुरंत समाधान करेगा। जनगणना आयुक्त ने जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है, जिससे लोग मैसेज भेजकर तुरंत सही और सटीक जानकारी पा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आम जनता और गणना करने वाले कर्मचारियों, दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।

अमेरिका के युद्धनीति वाले इतिहास का एक और दौड़ बीत गया?

अभिनय आकाश

दुनिया का रहनुमा, लोकतंत्र का प्रहरी, आतंकवाद का दुश्मन और खुद को सुपरपॉवर मुल्क मानने वाले देश के लुट-पिट कर लौटने की दास्तां है। कोरिया के पहाड़ों से लेकर वियतनाम के जंगलों और मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तानों तक, अमेरिकी सेना की भूमिका हमेशा चर्चा और विवाद का केंद्र रही है। अक्सर यह बहस छिड़ती है कि इन लड़ाइयों का असली मकसद लोकतंत्र की रक्षा था या फिर अपने भू-राजनीतिक दबदबे को बनाए रखना। अमेरिका का इतिहास सैन्य हस्तक्षेपों और रणनीतिक संघर्षों की एक लंबी गाथा रहा है। दुनिया भर के तमाम युद्धों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अमेरिका की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अमेरिका का दूसरे देशो में दखलअंदाज और भूमिका को लेकर सवाल अमेरिका के भीतर और बाहर, दोनों जगह भी उठते रहे है।

25 जून नॉर्थ कोरिया पीपल जमी यानी बक 75000 सोल्जर्स 38 पैरेलल को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर आक्रमण कर देते हैं और यही से कोल्ड वॉर की पहली मिलिट्री तस्सेल की शुरुआत होती है है इसकी इंटेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है की मानो इसको तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां एक तरफ था नॉर्थ कोरिया जिसको यूएसएसआर का सपोर्ट हासिल था तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया जिसको उस सपोर्ट कर रहा था। कोल्ड वॉर एशिया में कोरियन पेनिनसुला के बीच से होकर गुजारा रहा था। सोवियत संघ चाहता था की कम्युनिज्म नॉर्थ कोरिया से आगे बढ़कर जापान साउथ ईस्ट एशिया और बाकी पूरे एशिया में फैल जाए। लेकिन अमेरिका को ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। अमेरिका और यूएसएसआर की इसी जद्दोजहदका नतीजा हमें सबसे पहले कोरियन वॉर के रूप में देखने को मिला। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक

बॉन्ब गिरा दिए और जापान इस न्यूक्लियर हमले से पुरी तरह टूट गया। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर कर दिया और ये वॉर खत्म हो गई। जापान को कोरियर समेत अपनी सभी कॉलोनी को छोड़ना पड़ा। अब कोरिया जापान के चंगुल से तो आजाद हो गया, लेकिन उसके लिए तो असली युद्ध अब शुरू होने जा रहा था। असल में जैसे ही जापान ने कोरिया में सरेंडर किया वैसे ही सोवियत संघ ने नॉर्थ की तरफ से और अमेरिका ने साउथ की तरफ से आकर इसको कैप्चर कर लिया। इन दोनों ने अपनी सहमति से इस पेनिनसुला को 38 पैरेलल के अगेंस्ट दो हिस्सों में बांट दिया। नार्थ वाला हिस्सा सोवियत और साउथ वाला अमेरिका के पास चला गया। यह केवल 5 सालों के लिए एक टेंपरेरी अरेंजमेंट किया गया कमीशन के हाथों में सौंप दिया गया 1943 में हुई गए कॉन्फ्रेंस में ही यह तय कर लिया गया था की 5 साल बाद कोरिया को आजाद कर दिया जाएगा।1948 में नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से दो अलग-अलग नेशंस में डिवाइड हो गए नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म की सपोर्टर किम एल्सन और साउथ कोरिया में केपीटलाइज्म की सपोर्टर सिंह मैन रे प्रेसिडेंट बने। इन दोनों ही लीडर्स को अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा जानबूझकर चुना गया था और दोनों ने ही इन लीडर्स को अपने अपने रीजंस में हीरो की तरफ प्रमोट किया। धीरे-धीरे अमेरिकन और सोवियत ट्रूप्स को यहां से विद्रोह कर लिया गया। लेकिन यह स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए सेना भी भेजी। माना जाता है कि करीब 17,89,000 अमेरिकी सैनिको ने इसमें हिस्सा लिया। एक आकड़े के मुताबिक 33,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए।1955 में उत्तरी वियतनाम ने जब दक्षिणी भाग पर सैन्य जमावड़ा शुरू किया तो अमेरिका ने कम्युनिज्म के फैलने से रोकने के लिहाजे से सैन्य कार्रवाई छेड़ दी। 1967 तक वियतनाम में अमेरिकी फौजियों की संख्या 5 लाख को पार कर गई। लेकिन 1969 आते-आते घरेलू दबाव की वजह से अमेरिकी ने वियतनाम से बाहर निकलने का मन बना लिया। 20 सालों की जंग के दौरान कई बार संधि पर समझौते हुए और सब बेकार हो

खदान पर निरीक्षण करने गए भोजराज नाग ने अफसरों को दी गाली

भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम कच्चे स्थित आरी डोंगरी लौह खदान में मलबा धंसने की घटना अब सियासी रंग ले चुकी है। हादसे ने जहां स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं सांसद भोजराज नाग के बयान ने माहौल को और गरमा दिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रबंधन को फटकार लगाते हुए गंदी गालियां दी है। जानकारी के अनुसार 10-11 अप्रैल की दरम्यानी रात खदान से मलबा धंसकर एक मकान पर जा गिरा। घटना के बाद खदान प्रबंधन ने एहतियातन आसपास के 23 मकानों को खाली कराने और प्रभावित परिवारों को अन्य स्थान पर

बसाने का निर्णय लिया। साथ ही नए घर बनाने का आश्वासन भी दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान के कारण लगातार खतरा बना हुआ है, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थायी पुनर्वास दिया जाए। इस बीच कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग आज घटना स्थल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खदान प्रबंधन पर जमकर नाराजगी जताई और गाली देते हुए अमर्यादित बात कही। मौजूद लोगों के मुताबिक सांसद का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से तीखी भाषा का इस्तेमाल कर दिया।अब सवाल उठ रहे हैं कि यह बयान महज गुस्से में निकला या फिर यह एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था।राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। घटना स्थल पर मौजूद भीड़ के बीच सांसद की नाराजगी का वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

समस्याओं का जल्द समाधान करने के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान सांसद ने लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कंपनी प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। फिलहाल प्रशासन और कंपनी प्रबंधन राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए गए?

नाग ने अफसरों से कहा था ङ्क नींबू काटकर भूत उतार दूंगा

इससे पहले भी सांसद भोजराज नाग का विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो अधिकारी जनता की समस्याओं पर फोन नहीं उठाएंगे और शिकायतों का समाधान नहीं करेंगे, हम सभी के लिए नींबू काटेंगे। अवैध उत्खनन को लेकर सांसद भोजराज नाग ने कहा था कि जहां भी इस प्रकार का अवैध कारोबार होगा।

धमतरी में सोशल मीडिया क्रिएटरों को मिला मार्गदर्शन: मनोज डे ने साझा किए सफलता के सूत्र

धमतरी। जिले में आयोजित युवा फेस्ट के दौरान देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर मनोज डे का आगमन स्थानीय डिजिटल क्रिएटरों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। गुरुवार शाम लोहरशी रेस्ट हाउस में जिले के यूट्यूबर, ब्लॉगर एवं सोशल मीडिया क्रिएटरों ने उनसे सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान वातावरण उत्साह, जिज्ञासा और सीखने की ललक से परिपूर्ण रहा। प्रसिद्ध यूट्यूबर मनोज डे का आज पी.जी. कॉलेज में प्रसिद्ध यूट्यूबर संबंधी जानकारी युवाओं को देंगे । मुलाकात के दौरान मनोज डे ने उपस्थित युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म की

संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में सोशल मीडिया न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि आय अर्जन का एक सशक्त साधन भी बन चुका है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण, वीडियो में निरंतरता, दर्शकों की रुचि को समझने तथा प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म के अनुरूप कार्य करने के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि समर्पण, धैर्य और सही रणनीति के साथ कार्य किया जाए, तो डिजिटल क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही उन्होंने क्रिएटरों को मौलिकता बनाए रखने, सकारात्मक कंटेंट प्रस्तुत करने और नियमित रूप से स्वयं को अपडेट करते रहने की सलाह दी। जिले के युवा क्रिएटरों ने इस अवसर को अत्यंत उपयोगी बताया और कहा कि उन्हें व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपने कार्य को नई दिशा दे सकेंगे।

अंतराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश

- **घर में घुसते सीसीटीवी में कैद 4-5 नकाबपोश, धमतरी के साथ कोरबा-अंबिकापुर में भी वही पैटर्न**

धमतरी। शहर के आकाशगंगा कॉलोनी में हुई सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं का धमतरी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश के धार जिले से जुड़े एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

पुलिस ने गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द

गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने किया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी जिसमें 4-5 आरोपी घर में घुसते दिखे। दरअसल, 07 और 08 फरवरी 2026 की दरमियानी रात आकाशगंगा कॉलोनी में चार अलग-अलग मकानों में चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। ये सभी मकान थाना कोतवाली से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित हैं। घटना के समय घरों के सदस्य या तो मेले में गए हुए थे या किसी कारणवश घर पर मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाया। इन घटनाओं के संबंध में 08 से 10 फरवरी के बीच थाना कोतवाली में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। पीड़ितों में तुलसी राम ध्रुव, विकास कटेन्द्र, रूपेन्द्र कुमार साहू और उत्तम कुमार तिवारी शामिल हैं।

पांडुलिपियों को सहेजने की पहल

कोरिया। जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद कोरिया जिला प्रशासन ने भी इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिलेवासियों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा है कि जिनके पास 70 वर्ष से अधिक पुरानी

कोरिया जिले में ही 93 की पहचान

हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, वे इसकी जानकारी प्रशासन को अवश्य दें। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है और इसे सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है। पांडुलिपि संरक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए डिप्टी कलेक्टर उमेश कुमार पटेल को नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारी (पुरातत्व एवं पर्यटन शाखा) नियुक्त किया गया है। साथ ही एक विशेष समिति का गठन किया गया है और सर्वेक्षण के लिए 68 सर्वेयर्स की तैनाती की गई है। ये सर्वेयर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पांडुलिपियों की पहचान और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अब तक जिले में कुल 93 पांडुलिपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 63 पांडुलिपियों का विवरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है। हाल ही में 16 नई पांडुलिपियों को भी जोड़ा गया है।

स्कूली बच्चों ने सीखी सीपीआर

- **स्कूली बच्चों ने सीखी सीपीआर, सांप के डसने पर प्राथमिक उपचार के अलावा जीवन रक्षक कौशल की तकनीक, एनडीआरएफ की टीम ने दिया प्रशिक्षण**

गरियाबंद। भुवनेश्वर से आई एनडीआरएफ की टीम ने देवभोग में एनसीसी कैडेट और स्कूली छात्रों को आपदा प्रबंधन और जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण दिया, जिससे वे आपातकाल में किसी व्यक्ति की मदद कर सकें। भुवनेश्वर से पहुंची 3 बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने देवभोग और जामगांव हाईस्कूल में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर एनसीसी कैडेट्स, स्थानीय वालिंटियर छात्र एवं समाज सेवकों को आपदा प्रबंधन एवं जीवन रक्षक कौशल पर प्रशिक्षण दिया। बटालियन के सबइंस्पेक्टर वी के मीणा के नेतृत्व में टीम के मास्टर ट्रेनर राकेश पोथल, एसके साहू, पार्थ साईं ने आपदा की स्थिति में प्राथमिक उपचार, सीपीआर, गला घुटने की स्थिति में बचाव, खून बहने की स्थिति में नियंत्रण, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार, बादल फटने के दौरान सुरक्षा उपाय के अलावा बाढ़ के दरम्यान आने वाले दिक्कत और बचाव पर बुद्धिमता और साहस का परिचय देते हुए कैसे बचाव कार्य करे, इसकी एक-एक बारीकियों को बताया। डेमो और प्रायोगिक जरिए से कैडेट्स को बचाव की बारीकियों की जानकारी दिया। आयोजन को सफल बनाने में एनसीसी ऑफिसर गणेश सोनी, नोडल प्राचार्य सुरेश टांडीलय, संकुल समन्वयक सुरेश नारायण शुक्ला, केशरी कश्यप, कस्तूरबा अधिक्षक उष्णदेवी वैष्णव का विशेष योगदान रहा। आयोजन के उद्देश्य को बताते हुए टीम लीडर वीके मीणा ने कहा इस कार्यक्रम के जरिए समुदाय की आपदा सहनशीलता बढ़ाना,सुरक्षा के लिए प्रेरित करना, आपातकाल के स्थिति से निपटने व्यवहारिक कौशल में निपुण करना है।

बीएसपी में सौंदर्यीकरण के साथ जागरूकता की पहल

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र के सिविल इंजीनियरिंग विभाग (सीईडी) द्वारा संयंत्र परिसर में सौंदर्यीकरण के साथ सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक पहल की जा रही है। इसी दिशा में गैरेज रोड, स्लैग गैलरी से एमआरडी चौक तक की दीवारों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग का कार्य किया गया है, जिसमें मुख्यत: सुरक्षा संबंधी संदेशों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को स्थान दिया गया है।

कैंसर पीड़ित पत्नी को बाइक पर लेटाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पति

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के काटाबहरा निवासी समलू मरकाम अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी कपूरा मरकाम को बाइक में लिटाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनकी पत्नी कपूरा मरकाम थायराइड कैंसर के चौथे स्टेज से पीड़ित हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मरीज को हर संभव बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्थिति की गंभीरता को

मामला सुन कलेक्टर ने दिए निर्देश

देखते हुए महिला को रायपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी है। शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को महिला को रायपुर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पीड़िता का इलाज वर्ष 2024 से लेकर अप्रैल 2026 तक लगातार जारी है। रायपुर के एम्स, मेकाहारा, डीकेएस अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में उनका उपचार कराया गया। जनवरी 2025 में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भी करीब एक माह तक इलाज चला था। नवंबर 2025 में हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची थी। तब 108 एम्बुलेंस से महिला को रायपुर भेजा गया था, जहां एम्स में कीमोथेरेपी दी गई थी। उपचार के बाद महिला घर लौट आई थी, लेकिन अब एक बार फिर तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। समलू मरकाम का यह संघर्ष केवल बीमारी से नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी से भी जुड़ा है। पत्नी को बाइक में लिटाकर इलाज के लिए लाना उनकी मजबूरी को स्पष्ट दर्शाता है। हालांकि, प्रशासन की त्वरित पहल से अब बेहतर इलाज की उम्मीद जगी है। डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जल्द ही महिला को रायपुर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहां विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज करेगी। इस घटनाक्रम ने एक ओर जहां सिस्टम की संवेदनशीलता को सामने लाया, वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों की भी तस्वीर पेश की।

वेदांता हादसे में 25 वीं मौत

सक्ती। वेदांता हादसे में मौत का आंकड़ा 25 पहुंच गया है। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत की खबर से परिजनों व श्रमिकों में आक्रोश का माहौल है। रायपुर के निजी हास्पिटल में उपचाररत विश्वजीत साहू की मौत हो गई है। अभी भी गंभीर हालत में दाखिल श्रमिकों में कुछ की स्थिति काफी नाजुक बतायी जा रही है। चिकित्सकों की माने तो झुलसे हुए मजदूरों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस बात को लेकर अभी भी नाराजगी बनी हुई है कि घोषित मुआवजा पर्याप्त नहीं हैं।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़

कांग्रेस नेता के घर घुसे अज्ञात लोगों की फायरिंग से बेटे की मौत

जांजगीर-चांपा। जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत करही गांव में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बदमाश लूट की नीयत से घर में दाखिल हुए थे।यह घटना सीमेंट-रेत व्यवसायी एवं ब्लाक कांग्रेस उपाध्यक्ष सम्मेलाल कश्यप के घर की है। देर रात बदमाश घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को निशाना बनाते हुए अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के दौरान बड़े बेटे आयुष कश्यप को दो गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं छोटे बेटे आशुतोष कश्यप को भी गोली लगी, जो उसके दाहिने हाथ में लगी है। घटना के दौरान आरोपियों ने घर के अन्य सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर दिया, ताकि कोई मदद के लिए बाहर न निकल सके। गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

शासकीय जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, बाप-बेटों ने लाठी

जशपुर। जिले के पंडरा पाठ के गांव अम्बाडीपा में शासकीय काबिज जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद हिंसक रूप में बदल गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। मामला थाना बगीचा क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी जवाहर यादव (37 वर्ष) निवासी ग्राम अम्बाडीपा ने चौकी पंडरा पाठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उनका परिवार पूर्वजों के समय से घर के पास स्थित शासकीय काबिज जमीन का उपयोग खलिहान और गोठान के रूप में करता रहा है। इसी जमीन को लेकर गांव के ही मदन यादव, ठाकुर दयाल यादव एवं सत्यपाल यादव (बाप-बेटे) लगातार अपना हक जताते हुए विवाद करते रहे हैं और जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराने का दावा करते हैं। दिनांक 20 अप्रैल की सुबह करीब 9.30 बजे प्रार्थी पक्ष के परिवारजन भतीजी प्रतिभा, भतीजा मिथलेश, बेटी मंजू यादव और बेटा संदीप यादव सहित अन्य सदस्य खलिहान में पैरा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी पक्ष भी वहां मौजूद था। जमीन को लेकर फिर विवाद बढ़ा।

साल में एक बार खुलती है छत्तीसगढ़ की ये गुफा

खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई क्षेत्र के ठाकुरटोला जमीदारी में स्थित मण्डीप खोल गुफा एक बार फिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनने जा रही है। साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाली यह गुफा 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोली जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है, क्योंकि इस दिन यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। मण्डीप खोल गुफा की खास बात यह है कि यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्य और परंपरा से जुड़ा एक अनोखा स्थान है। मान्यता है कि यह गुफा अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को ही खुलती है और इसी दिन यहां भगवान शिव के दुर्लभ दर्शन होते हैं। गुफा खुलने के बाद सबसे पहले ठाकुरटोला राजपरिवार द्वारा पूजा-अर्चना की जाती है, इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू होते हैं। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित इस गुफा तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

बस्तर मुन्ने के तहत पर आयोजित की जाएंगी कार्यक्रम

उत्तर बस्तर कांकेर। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'बस्तर मुन्ने' (अग्रणी बस्तर) अभियान का चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आगामी 01 मई से जिले की सभी ग्राम में विशेष 'संतृप्तता शिविरों' का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने उक्त अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं समाज के वंचित वर्गों तक उनका समयबद्ध लाभ के लिए बस्तर संभाग के सभी 07 जिलों में 'बस्तर मुन्ने' अभियान के अंतर्गत संतृप्तता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मूल उद्देश्य एनसीएईआर सर्वेक्षण में नियद नेल्लानार अंतर्गत 31 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित परिवारों को शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाना है।

लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कलेक्टर व एसपी ने ली समीक्षा बैठक

मोहला। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने नशा नियंत्रण और जनसुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने आगामी सुशासन तिहार 2026 के दौरान जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। कलेक्टर ने एन-कॉर्ड की समीक्षा करते हुए जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों से उपचार लेकर लौटे व्यक्तियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि उनका सतत फॉलो-अप के साथ ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे तथा समाज में जागरूकता फैलाने के प्रयास करे।

30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मोहला। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है । इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। इसके अंतर्गत पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले में नया नलकूप

खनन कर सकेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु किए गए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के अनुमति देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व अनुविभाग मोहला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला को एवं राजस्व अनुविभाग मानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अवैध शराब की बिक्री रोकने चुना अनोखा रास्ता

डोंगरगढ़। जहां एक ओर प्रदेशभर में शराब दुकानों के विरोध की आवाजें उठती रहती हैं, वहीं डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कल्याणपुर ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। यहां के ग्रामीण अब अपने गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है वर्षों से जारी अवैध शराब का कारोबार। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई। नतीजा यह हुआ कि अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही नया रास्ता

चुना। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों ने गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग की है। इसके लिए शासकीय जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री, कलेक्टर व एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का साफ कहना है कि सरकारी दुकान खुलने से अवैध शराब बेचने वालों की कमर टूटेगी और गांव में गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब सिस्टम विफल होता है, तो लोग समाधान के लिए असामान्य लेकिन व्यावहारिक रास्ते तलाशने लगते हैं। डोंगरगढ़ शहर में एक विवादित पोस्टर सामने आया है, जिसमें खुले तौर पर शराब की विभिन्न किस्मों की 24 घंटे उपलब्धता का दावा करते हुए कुछ होटलों और व्यक्तियों के नाम व स्थान का उल्लेख किया गया है। पोस्टर में न केवल अवैध गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, बल्कि पुलिस से संरक्षण जैसे आपत्तिजनक दावे भी लिखे गए हैं, जो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

अम्बिकापुर में प्लास्टिक-पटाखे की दुकान में भीषण आग

अंबिकापुर। अंबिकापुर में प्लास्टिक-पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। यहां मुकेश प्लास्टिक की होलसेल शॉप है। जहां लाखों रुपए के प्लास्टिक के सामानों और पटाखों का भंडारण है। 1 घंटे के अंदर आग ने 2 मंजिला बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। 10 किमी दूर से दिख रहा धुएं का गुबार, कलेक्टर बोले- जनहानि नहीं, आग बुझाने की कोशिश जारी हैं। अग्निशमन अमला के साथ आसपास के लोगों ने आग बुझाने में काफी मशक्कत की। फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चला है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से फिल परमार्थ आश्रम के संस्थापक ने की भेंट

रायपुर। रमेन डेका से शुक्रवार को फिल

परमार्थ आश्रम, भिलाई के संस्थापक श्री अमित राज ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आश्रम की गतिविधियों एवं समाजसेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। आश्रम द्वारा सड़कों पर लावारिस अवस्था में घूम रहे बुजुर्गों तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का रेस्क्यू कर उन्हें आश्रम में आश्रय दिया जाता है। वहां उनके उपचार, देखभाल, भोजन तथा आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक आश्रम के माध्यम से 208 लोगों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में आश्रम में 94 लोग निवास कर रहे हैं, जिनकी नियमित देखरेख की जा रही है।उन्होंने राज्यपाल से आश्रम का भ्रमण करने का आग्रह भी किया। राज्यपाल ने आश्रम द्वारा किए जा रहे मानवीय एवं सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया। उल्लेखनीय की राज्यपाल द्वारा इस संस्था को पूर्व में 2 लाख रुपए का स्वेछानुदान भी प्रदान किया गया है। इस अवसर पर आश्रम के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

सट्टेबाजी गिरोह के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी के घर क्राइम ब्रांच का छापा

रायपुर। ऑनलाइन सट्टा एप '3 स्टंप' से जुड़े

बड़े नेटवर्क पर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एप के मास्टरमाइंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी के निवास पर क्राइम ब्रांच और गंज थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई में डीएसपी, टीआई समेत वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने घर और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश देकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बाबू खेमानी के विदेशी नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस पिछले एक घंटे से लगातार तलाशी और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है।

बायलर हादसा : एनएचआरसी ने दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली-रायपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सक्ती जिले में संचालित वेदांता बायलर हादसा मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए दोनों अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दिए जा रहे मुआवजे की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने कहा है। इसके अलावा आयोग ने ये भी पूछा है कि हादसे के कारणों की जांच कहां तक पहुंची है और दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक संबंधी आदेश सरकार ने लिया वापस

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय

कर्मचारियों की राजनीतिक सक्रियता को लेकर जारी आदेश को महज एक दिन के भीतर वापस लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह आदेश 24 घंटे भी प्रभावी नहीं रह सका और अगले ही दिन इसे स्थगित कर दिया गया। दरअसल, सरकार ने हाल ही में एक निर्देश जारी कर स्पष्ट किया था कि शासकीय कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से सक्रिय रूप से नहीं जुड़ सकेंगे। आदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, पद धारण करने और किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिका पर रोक की बात कही गई थी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि आदेश जारी होने के तुरंत बाद सरकार ने यू-टर्न लेते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इस अप्रत्याशित फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतनी जल्दी अपना फैसला बदलना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारी संगठनों की आपत्तियों और आदेश की व्याख्या को लेकर उठे सवालों के बाद सरकार ने फिलहाल पीछे हटना उचित समझा। फिलहाल आदेश वापस होने के बाद कर्मचारियों के बीच राहत है, लेकिन यह मामला अब सियासी बहस का विषय बन गया है।

भीषण गर्मी में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि : मंत्री राजवाड़े

■आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक होंगे संचालित

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ेप्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित और संवेदनशील निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के स्पष्ट निर्देश पर ग्रीष्मकाल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव करते हुए इसे 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है।

निर्देशानुसार 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रात: 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगे। विशेष रूप से 23 अप्रैल से 30 जून 2026 तक बच्चों की उपस्थिति का समय केवल सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि वे भीषण गर्मी और लू के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें।

इस निर्धारित अवधि में बच्चों को पूर्व तय समय-सारिणी के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (श्वष्टष्टश्व गतिविधियां) के साथ-साथ पूरक पोषण आहार का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्य आवश्यक सेवाएं प्रात: 11:00 बजे तक जारी रहेंगी। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने निर्धारित जॉब चार्ट के अनुसार शेष कार्यों का निष्पादन करेंगी। साथ ही, गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श देने की महत्वपूर्ण सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कार्यकर्ता केंद्र बंद होने के बाद घर-घर जाकर माताओं को जागरूक करेंगी।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गर्म हवाओं और उच्च तापमान के बीच बच्चों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही, सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करें और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करें, ताकि जमीनी स्तर पर निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ग्रीष्मकाल समाप्त होने के बाद 01 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्र पुन: अपने सामान्य समय प्रात: 9:30 बजे से 3:30 बजे तक (6 घंटे) संचालित होंगे।

कोडीन सिरप का फर्जी कारोबार करने वाले मुख्य सरगना गिरफ्तार

दुर्ग। प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के एक संगठित गिरोह का चौकी स्मृतिनगर और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 800 नग सीएडीआईएफओएस टी सिरप सहित 5 लाख रुपये का अन्य सामान जप्त किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को चौकी स्मृतिनगर क्षेत्र के ग्राम जुनवानी खम्हरिया रोड के पास तीन लोगों द्वारा प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप ले जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर चौकी स्मृतिनगर और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर सेण्ट्रो कार (क्रमांक सीजी-07/8595) को रोका। तलाशी में कार से सात कार्टून में रखे सीएडीआइएफओएस टी नामक सिरप बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी योगेश शर्मा और उमेश कुमार यादव ने बताया कि वे फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कर गुजरात की कंपनियों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट और ई-कुरियर के माध्यम से नशीली सिरप मंगाते थे। इसके बाद इन सिरप को अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी योगेश शर्मा ने एक असली ड्रग लाइसेंस में एडिटिंग कर अपने नाम से फर्जी लाइसेंस तैयार किया था, साथ ही फर्जी लेटरपैड और सील बनवाकर इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था।

राज्यपाल ने कोसा वस्त्रों के नवाचार और बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया जोर

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा साड़ी, शाल और गमछा का अवलोकन किया तथा राज्य के हाथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए नवाचार, डिज़ाइन विकास और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोसा साड़ी एवं शाल में डॉबी और जैकार्ड तकनीक का उपयोग कर आधुनिक डिज़ाइन विकसित किए जाएं। साथ ही विभिन्न आयु वर्ग की पसंद को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को आकर्षक एवं किफायती बनाया जाए, ताकि इनकी बाजार में मांग बढ़ सके।

उन्होंने उत्तर-पूर्व के प्रसिद्ध रेशम क्षेत्र असम के सुवालकुची, विजयनगर और डेमाजी क्षेत्रों के सफल मॉडल का अध्ययन कर वहां के लोकप्रिय डिज़ाइनों को छत्तीसगढ़ के कोसा वस्त्रों में समाहित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि इससे राज्य के बुनकरों को नई पहचान मिलेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

राज्यपाल ने कोसा साड़ी को अधिक किफायती बनाने के लिए साड़ी की बॉडी और बॉर्डर को पृथक रूप से तैयार कर नई शैली की साड़ियों के निर्माण का सुझाव भी दिया। उन्होंने विशेष रंगों एवं धागोंकृएक्रेलिक, स्पन और टू-प्लाई यार्न का उपयोग कर आकर्षक मोटिफ और डिज़ाइन विकसित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने आगामी एक माह में इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामोद्योग विभाग को राज्य की किसी एक बुनकर सहकारी समिति को गोद लेकर उसके समग्र विकास हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री श्याम धावड़े, राज्य हाथकरघा संघ के सचिव श्री एम. एम. जोशी, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार बुनकर सेवा केंद्र रायगढ के उपनिदेशक श्री विजय सावनेरकर सहित तकनीकी विशेषज्ञों तथा डिज़ाइनर उपस्थित रहे।

सीजी बोर्ड का परीक्षा परिणाम जल्द जारी होगा

रायपुर। कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) 30 अप्रैल या एक मई को परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। काउंटिंग, मिलान और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

बता दें कि इस बार हिंदी का पेपर लीक होने की वजह से कक्षा 10वीं की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को दोबारा आयोजित की गई थी। इस कारण परीक्षा परीणाम जारी होने में देरी हो रही है।

माशिमं की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि मूल्यांकन का कार्य समय पर हो चुका है। फिलहाल, मिलान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कोई गलती न हो, इसे लेकर सावधानी बरती जा रही है । कार्य की गति को देखते हुए उम्मीद है कि 30 अप्रैल या एक मई तक रिजल्ट जारी हो सकता है।

कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर और 13 मार्च 2026 तक पूरी हुई। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 को खत्म हुई।

कक्षा दसवीं में 3,20,535 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। वहीं कक्षा 12वीं में 2,45,785 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। कुल मिलाकर करीब 5.66 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे।

छात्र रिजल्ट जानने के लिये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट्स cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसके साथ ही DigiLocker पर भी मार्कशीट उपलब्ध रहेगी।

निजी भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर निगम को देना होगा शुल्क

■ शासकीय प्रदर्शनी एवं शासकीय आयोजन इस शुल्क के छुट के दायरे में आएंगे

रायपुर। नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क नगर निगम को देना होगा।शासकीय आयोजन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम बाजार विभाग की ओर से आदेश जारी कर नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रदर्शन कर की दरों में मेयर इन काउंसिल का संकल्प क्रमांक-23 पारित 8 जनवरी एवं सामान्य सभा का संकल्प क्रमांक - 13 - 10 अप्रैल 2026 में किये गये निर्णय अनुसार वृद्धि की गई दरों की सूची जारी कर दी है।

सूची के अनुसार सिनेमा गृह 50 रुपये प्रति शो यथावत, सर्कस 100 रुपये प्रति शो यथावत, जादूगर 200 रूपये प्रति शो यथावत, मॉल 600 रूपये प्रति शो, मीना बाजार (प्रदर्शन शुल्क) 500 रूपये प्रतिदिन यथावत, प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला उद्योग मेला एवं अन्य (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू प्रतिदिन, मीना बाजार / प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला / उद्योग मेला एवं अन्य (अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क) इन सभी के आयोजन में बहुत बड़े क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग होता है एवं इस भूमि से नगर निगम को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। अतः भूमि चाहे निजी हो या शासकीय प्रति 10 हजार वर्गफूट तक का भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क लिया जावेगा। यह शुल्क प्रति 10 हजार वर्गफीट पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जावेगा। चूंकि सभी आयोजनों का आकार अलग-अलग होता है अत क्षेत्रफल के अनुसार से दर निर्धारित किया गया है। शासकीय प्रदर्शनी एवं शासकीय आयोजन इस शुल्क से छूट के दायरे में आयेगें।

आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदर्शन कर एवं अतिरिक्त प्रदर्शन करों की वृद्धि उपरांत दरों को 11 अप्रैल से प्रभावशील कर दिया गया है। मॉल के सिनेमाघरों के प्रदर्शन शुल्क वृद्धि प्रति स्कीन प्रति शो के अनुसार देय रहेगी । जारी आदेशानुसार प्रदर्शन कर की नवीन दरों के अनुरूप वसूली किये जाने के आदेश नगर निगम आयुक्त ने जारी किए है।

खेल मंत्रालय के तीन दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने उप मुख्यमंत्री साव श्रीनगर रवाना

■ शिविर में भारत को 2047 तक खेलों में भी अग्रणी देश बनाने पर होगा मंथन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव शुक्रवार सुबह श्रीनगर में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय (24, 25, 26) चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इससे पहले श्री साव ने नवा रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा कर चिंतन शिविर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने आगामी समय में खेलों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों, खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के विषय में विचार-विमर्श किया जाएगा।

साव ने बताया कि, इस तीन दिवसीय शिविर में सभी राज्यों के खेल मंत्री और अधिकारी मंथन कर खेलों के विकास के लिए योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, ऐसे ही 2047 तक हमारा देश दुनिया में खेल के क्षेत्र में अग्रणी बने, इस लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। जिसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि, 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने देश की आधी आबादी के साथ षड्यंत्र करके उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आएगा। नगरीय निकायों में सामान्य सभा और इसी तरह पंचायतों में निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। देश की आधी आबादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी।

साव ने कांग्रेस द्वारा खिलाड़ियों को लेकर किए बेबुनियाद सवाल पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पांच साल सत्ता में रहने के बावजूद खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। उसे सवाल करने से पहले अपना हिसाब प्रस्तुत करने चाहिए। पांच साल खिलाड़ियों को खेल अलंकरण तक नहीं दे सकें। अब किस मुंह से सवाल कर रहे हैं।

रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर संरक्षा सेमिनार का आयोजन

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग द्वारा ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन हेतु परिचालन, विद्युत परिचालन, यांत्रिक, इंजीनियरिंग तथा राजभाषा विभाग के कर्मचारियों के साथ मल्टी फंक्शन काम्पलेक्स, दुर्ग स्टेशन में शुक्रवार को संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

स्पैड से बचाव एवं ऑटोमेटिक सिगनल फेलुअर के दौरान दी जानेवाली प्राधिकार और चालक द्वारा लिए जानेवाली सावधानियां, शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियां एवं पावर ब्लाक के दौरान स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां, विद्युतीकृत सेक्शन एवं विद्युतीकृत पिट में कार्य करने के दौरान लिए जानेवाली सावधानियां, इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा बरती जाने वाली गर्मीकालीन सावधानियां एवं कार्यस्थल की संरक्षा, एल एच बि कोच वाली ट्रेन परिचालन के दौरान होने वाली असामान्य घटनायें एवं उसका निवारण, ट्रेन में आग लगने का कारण एवं उसका निवारण, राजभाषा हिंदी का महत्व एवं संरक्षा में योगदान, प्राथमिक उपचार पेटी के उपयोग का प्रदर्शन तथा अग्निशामक यंत्र का उपयोग एवं प्रदर्शन।

इस संरक्षा सेमिनार में प्रवीण कुमार, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी/रायपुर, निकेश कुमार पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी/रायपुर के साथ-साथ संरक्षा सलाहकारो ने संरक्षा सेमिनार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संरक्षा संगठन/रायपुर मंडल के द्वारा प्रत्येक माह में 2 संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन रायपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों में किया जाता है, जिससे कर्मचारियों में कार्य करने के दौरान संरक्षा के प्रति जागरुकता लाई जा सके। उक्त संरक्षा संगोष्ठी में संरक्षा सलाहकार, सुपरवाइजर एवं फील्ड कर्मचारियों को मिलाकर कुल 64 लोगों ने भाग लिया।

शिक्षक सुसाइड मामला : कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन-विक्रम मंडावी

■भाजपा जिलाध्यक्ष बोले- दोषियों को मिलनी चाहिए सजा

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शिक्षक आत्महत्या मामले में अब राजनीति गरमाई गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हो गए हैं। बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने आज प्रेसवार्ता कर भाजपा नेता, सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर समाज के लोगों के साथ मिलकर बीजापुर थाने का घेराव करने की बात भी कही। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने भी मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल बीते बुधवार चेरपाल निवासी व पालनार स्कूल के प्रधान अध्यापक राजू पुजारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस जांच में मृतक के पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने तीन लोग देवाशीष मंडल (ठेकेदार) शैलेष वासम, डोंगरे सर को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। नोट में यह भी लिखा है कि 'मेरे परिवार की जिम्मेदारी ये लोग ही उठाएं। अब जिले में यह मामला गरमाया हुआ है।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि पालनार स्कूल में जो भवन निर्माण कराया गया है, उसकी लागत राशि लगभग 20 लाख 30 हजार रुपए है, जिसके भुगतान को लेकर यह सब घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया यह क` व ल आत्महत्या नहीं बल्कि निर्माण कार्य से जुड़े दबाव का परिणाम है। शिक्षक राजू पुजारी अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान थे, लेकिन स्कूल भवन के निर्माण को लेकर गहरी मानसिक चिंता में थे। विधायक ने कहा, पालनार में बन रहे स्कूल भवन के लिए 20 लाख 30 हजार रुपये स्वीकृत थे, लेकिन निर्माण कार्य बेहद घटिया गुणवत्ता का किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधूरे और निम्नस्तरीय निर्माण के बावजूद भुगतान का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे शिक्षक तनाव में आ गए।

विधायक मंडावी ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से मर्डर, लूटपाट, चोरी जैसे जघन्य घटनाएं हो रही है। यह घटना अपने आप में बहुत ही बड़ी है, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। इस घटना में जो नाम रजिस्टर और अन्य दस्तावेज बरामद हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से भाजपा नेता का नाम सम्मलित है। उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी मामले में संलिप्त हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक मंडावी ने कहा कि तीन दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो हम समाज और परिजनों के साथ बीजापुर थाना का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे।

वहीं मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने कहा कि यह घटना बेहद ही चिंताजनक है। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। घटना में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी/कांग्रेस की बात नहीं है, इसमें कोई भी राजनीति दल से शामिल हो उस पर पुलिस जांच कर कार्रवाई करें।

रजिस्ट्री को लेकर सरकार के दो अहम फैसले जमीन पर क्यों नहीं हो सके लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर राज्य सरकार के दो अहम फैसले अब तक जमीन पर लागू नहीं हो सके हैं। कैबिनेट ने रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60 प्रतिशत उपकर को खत्म करने और महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया था, लेकिन इन दोनों फैसलों पर अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। दरअसल, सरकार का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी पुराने नियमों के तहत ही शुल्क वसूला जा रहा है, यानी 0.60 प्रतिशत उपकर भी लिया जा रहा है, और महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब कैबिनेट ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है तो अधिसूचना जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ रहा है।

बंपर वोटिंग का संदेश: जनता की चुप्पी में छिपा जनादेश

कांतिलाल मांडोत

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और परिपक्वता को एक बार फिर रेखांकित किया है। भीषण गर्मी, लंबी कतारें और कई जगहों पर तनावपूर्ण माहौल के बावजूद जिस तरह मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वह सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी का सशक्त प्रदर्शन है। यह सवाल अब स्वाभाविक रूप से उठता है कि इतनी भारी वोटिंग का अर्थ क्या है—क्या यह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जनसमर्थन का संकेत है या फिर परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक? इतिहास बताता है कि अधिक मतदान को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कई बार ज्यादा मतदान सत्ता में बैठे दल के पक्ष में गया है, तो कई बार यह बदलाव की लहर का संकेत भी बना है। इसलिए इस बार भी केवल प्रतिशत के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जब सामान्य से कहीं अधिक मतदाता मतदान के लिए निकलते हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई मजबूत भावनात्मक या राजनीतिक कारण जरूर होता है। पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान का प्रतिशत 90% के पार चला गया, जो अपने आप में एक असाधारण स्थिति है। यहां चुनाव हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कभी-कभी हिंसक भी रहे हैं। इस बार भी छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का बड़ी संख्या में मतदान करना यह दर्शाता है कि वे अपने वोट के महत्व को समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। यहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और दोनों ही दल इस भारी मतदान को अपने-अपने पक्ष में बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि यह मतदान उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और कथित मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में जनता की प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे जनता की आवाज बताया है, जो उनके अनुसार बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव के खिलाफ है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी इसे परिवर्तन की लहर के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में दावा किया है कि जहां ज्यादा मतदान हुआ है, वहां भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही रोचक है। यहां परंपरागत रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच सीधी टक्कर रहती है। इस बार भी यही मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभिनेता विजय की नई पार्टी ने समीकरणों को थोड़ा जटिल बना दिया है। रिकॉर्ड मतदान को यहां स्पष्ट जनादेश की संभावना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर तमिलनाडु में जब मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होता है, तो मतदाता किसी एक पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाते हैं। इस बार के चुनावों में एक और महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। यह केवल संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का संकेत भी है। बंपर वोटिंग का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकलते हैं, तो यह संकेत होता है कि वे मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वे किसी बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। यह असंतोष भी हो सकता है और उम्मीद भी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह मतदान किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह सामान्य चुनाव नहीं है।

दीदी जाने वाली है भाजपा आने वाली है?

सनत जैन

भारत में आजादी के बाद पहली बार मतदान का एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, जो ना भूतो ना भविष्यति की तरह है। प्रथम चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है, प्रथम चरण की जिन 154 सीटों में जो मतदान हुआ है उसमें बीजेपी 120 सीटों पर जीत रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव का नॅरेटिव बनाकर महिला आरक्षण बिल को आधार बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। चुनाव के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन और जनगणना के मुद्दे पर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया था। बिल को महिला आरक्षण से जोड़कर प्रचारित किया गया। महिला आरक्षण बिल अस्तित्व में है। इसके बाद भी जब यह बिल संसद से दो तिहाई बहुमत से पास नहीं हो पाया। उसके बाद भाजपा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का मुद्दा बनाया। महिला आरक्षण के नाम पर बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया। जो मतदान हुआ है, उस पर भाजपा का दावा है, महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 86 फीसदी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तमिलनाडु में भी महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, यह दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के पहले, इसी तरह का नॅरेटिव बनाकर भाजपा अप्रत्याशित रूप से चुनाव जीतती रही है। इस बार भी भाजपा को भरोसा है, वह पश्चिम बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक इसके विपरीत ममता दीदी का दावा है। इस बार महिलाओं ने एसआईआर के नाम पर जिस तरह से करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। तार्किक विसंगति के नाम पर लगभग 64 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग किए गए हैं। बंगाल के मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प. बंगाल के करोड़ों मतदाता इस प्रक्रिया में काफी परेशान थे। अंतोगत्वा 34 लाख से ज्यादा मतदाताओं को प. बंगाल में मतदान से वंचित रखा गया है। इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया बंगाल में हुई है। मतदाताओं को अपनी नागरिकता बचाने के लिए जो परेशानी उसे हुई है। बंगालियों को जिस तरह से परेशान किया गया है। उससे नाराज मतदाताओं ने इस बार टीएमसी के पक्ष में मतदान किया है। बंगाली स्मिता और नागरिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, कम्युनिस्ट विचारधारा के मतदाताओं ने भी टीएमसी के पक्ष में मतदान किया है। ममता बनर्जी का दावा है, भारी संख्या में जो मतदान हुआ है। वह एसआईआर के विरोध और बंगाली अस्मिता को बचाए रखने के लिए हुआ है। ममता बनर्जी का दावा है, वह भारी बहुमत के साथ चौथी बार अपनी सरकार बनाने जा रही हैं।

बंगाल चुनाव पर गहरी नजर रख रहे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, इस बार का विधानसभा चुनाव परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला होगा। पिछले 15 वर्षों के चुनाव परिणाम को देखने पर स्पष्ट है। कम्युनिस्ट विचारधारा के मतदाता प्रत्येक चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे थे। इसका मुख्य कारण कम्युनिस्ट विचारधारा का कमजोर होना और भाजपा द्वारा सुनयोजित रूप से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना था। कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी के बीच में लगातार टकराव बढ़ने का फायदा भाजपा को पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार मामला उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है।

जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से देश में घुसपैठियों के नाम बंगालियों को निशाने पर लिया गया है। उसके कारण बंगाली अस्मिता और एसआईआर के विरोध में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने भारी मतदान किया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के पहिले भय का वातावरण, चुनाव के पहले चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों एवं हिंदू कट्टरता के नाम पर बनाया गया उससे पश्चिम बंगाल का मतदाता नागरिक अधिकारों को लेकर सजग हुआ है। पहली बार वामपंथी विचारधारा को छोड़कर ममता दीदी के पक्ष में मतदान किया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा परिवर्तन पहली बार होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का कमजोर होना पूंजीवादी व्यवस्था का मजबूत होना भाजपा के पक्ष में था। अब, जिस तरह से निम्न वर्ग नागरिकता, बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहा है, उससे पश्चिम बंगाल का मतदाता भाजपा से भारी नाराज है। प्रथम चरण के मतदान में जिस शांति के साथ भारी संख्या में घरों से निकलकर मतदाताओं ने मतदान किया है। उससे यह संकेत मिल रहा है, इस बार पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ होने जा रहा है, जो भविष्य में प. बंगाल एवं देश की राजनीति को नई दिशा देगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

बांग्लादेश के चुनाव में जिस तरह के हालत थे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना के पक्ष में काम किया था। उसके बाद बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ी। एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं के वोट काटने की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में हुई है। बंगाली समुदाय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर अभी तक के हर मामले में मुखर रहता आया है। प्रथम चरण के मतदान में जिस तरह के रुझान आए हैं, वह बहुत कुछ कह रहे हैं। परिणाम आने के बाद प्रदेश एवं देश में इसकी तीव्र राजनैतिक प्रतिक्रिया होना तय है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने सहित मतदाता सूचियों में सुधार के कारण मतदान में वृद्धि अपेक्षित थी। बिहार में भी हमने ऐसा ही पैटर्न देखा, जहां मतदान प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई, लेकिन सरकार नहीं बदली।

एसआईआर के दौरान नाम हटाए जाने से मतदाताओं की संख्या में लगभग 12 प्रतिशत की कमी आई है, जो इसका सबसे बड़ा कारण है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार हटाए गए लोगों में से लगभग 34 प्रतिशत मुस्लिम हैं।

पहले चरण में ट्रिब्यूनल द्वारा वैध घोषित मतदाताओं की संख्या मात्र 139 है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के निपटारे के लिए जजों ने केवल 657 मामलों का निपटारा किया जिनमें 139 को मंजूरी दी और 8 के नाम हटाए गए। तार्किक विसंगतियों के कारण हटाए गए लोगों की कुल संख्या 27.10 लाख में से लगभग 14 लाख लोग पहले चरण के मतदाता थे।

दरअसल, एसआईआर के बाद बड़ी मशक्कत से अपने मताधिकार को हासिल करनेवालों ने हर कीमत पर ईवीएम तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की। भारी गर्मी के बावजूद महिलाओं, प्रवासी मजदूरों समेत हर मतदाता ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। यह चुनाव उनके लिए अपनी अस्मिता की रक्षा ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों को बरकरार रखने का संघर्ष बन गया।

खासकर, मुस्लिम बहुल जिलों में भारी मतदान से भी पता चलता है कि अल्पसंख्यक मतदाता उत्साह के कारण नहीं बल्कि इस डर से टीएमसी के पीछे एकजुट हुआ है कि विभाजित वोट बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अल्पसंख्यक मतदाताओं में यह भावना बढ़ रही है कि वे टीएमसी से चाहे कितने भी असंतुष्ट क्यों न हों, वे अपने वोट को बंटने नहीं दे सकते, जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।

बहरहाल, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एसआईआर ने न केवल चिंता पैदा की है, बल्कि समुदाय को एकजुट करने का भी काम किया है। बीजेपी के घोषणापत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के वादे के बाद असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है।

अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और पहचान में हस्तक्षेप का प्रयास बताया है। एसआईआर में नाम को काटे जाने और यूसीसी के वादे के बाद मतदान में वृद्धि स्वाभाविक है। फतह किसकी होगी इसके लिए 4 मई तक इंतजार करना होगा!

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सजूरिन्द्रेण पंचाशद्देवास्ते मरुतोऽभवन्।
व्यपोह्यो मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः।।67।।
दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान्।
इन्द्रेण सहितान्देवी पर्य्यतुष्यदनिन्दिता।।68।।
व्रतमेतत्सुदुष्करम् ।।69।।
अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्।
अपत्यमिच्छन्त्यचरं एकः संकल्पितः पुत्रः
सप्तसप्ताभवन्कथम्?
यदि ते विदितं पुत्र! सत्यं कथय मा मृषा ।।70॥
इन्द्र उवाच अम्ब तेऽहं
व्यवसितमुपधार्य्यागतोऽन्तिकम्।
लब्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्म्मवित् ।।71।।
कृत्तो मे सप्तधा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः।
तेऽपि चैकैकशो वृक्णा सप्तधा नापि मस्त्रिरे ।।72।।
तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसि!
क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भोऽमृतोत्थितः
।।76।।
इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया।
मरुद्भिस्सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः ।।77।।
(श्रीमद्भागवत 6 । 18 ।)

अर्थात- एक दिन वह (दिति) पुंसवन व्रत से दुबली होते हुए भी भावी की प्रबलता से सांझ के समय भूठे मुख पाँवों को न धोकर सोगई ॥60॥ योगेश इन्द्र इस तरह व्रतभङ्ग से अवसर पाकर सोती हुई दिति के पेट में योगमाया द्वारा प्रविष्ट होगये॥ 61।। सोने की तरह दमकते हुए गर्भ को वज्र से काट कर इन्द्र ने सात टुकड़े कर डाले। रोते हुवे उन सातों खंडों को मा रोदीः ऐसे कहते हुवे फिर एक एक के सात खण्ड कर दिये।। 62।। तब वे कटे हुवे खण्ड अंजलि बाँधकर इन्द्र से कहने लगे कि आप हमें क्यों मारते हैं हम तो आपके भाई हैं।।63।। तब इन्द्र ने अपने अनन्य सेवक मरुद्गण से कहा कि अच्छा भ्राताओ! अब आप मुझते भयभीत मत होइये।। 64।। **क्रमशः ..**

विश्व मलेरिया दिवस

सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसी जानलेवा, घातक और व्यापक संक्रामक बीमारी के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम के उपायों को प्रोत्साहित करना, समय पर जाँच एवं उपचार की व्यवस्था पर बल देना तथा वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है।

मलेरिया को आज भी एक सामान्य रोग समझ लिया जाता है, किंतु यह आज भी विश्व की सबसे गंभीर जनस्वास्थ्य समस्याओं में से एक है और हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वायरस से नहीं बल्कि प्लास्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुँचता है। पाठक जानते होंगे कि हर मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता। मलेरिया शब्द की यदि हम यहां पर बात करें तो यह शब्द इतालवी(इटली) भाषा के माला एरिया से बना है, जिसका अर्थ खराब हवा होता है, क्योंकि प्राचीन काल में लोग मानते थे कि यह बीमारी गंदी या दूषित हवा से फैलती है, जबकि बाद में विज्ञान ने सिद्ध किया कि इसका वास्तविक कारण मच्छर हैं।

पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि मलेरिया कोई नया नहीं बल्कि, यह एक अत्यंत प्राचीन रोग है, जिसका उल्लेख प्राचीन मिस्र, भारत तथा चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। संक्रमित मच्छर के काटने पर प्लास्मोडियम परजीवी रक्त में प्रवेश कर लाल रक्त कोशिकाओं में बहुगुणित होने लगता है, जिससे रक्तहीनता (एनीमिया), कमजोरी और अन्य जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। बहरहाल, इसके प्रमुख लक्षणों की यदि हम यहां पर बात करें तो इसके प्रमुख लक्षणों में क्रमशः तेज बुखार, ठंड लगना, कंपकंपी, सिरदर्द, मतली, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, साँस फूलना, तेज नाड़ी, थकान, कमजोरी तथा जुकाम जैसी अनुभूति शामिल हैं। गंभीर अवस्था में रोगी मूर्च्छा तक में जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। कुछ लोगों में इसके लक्षण देर से प्रकट होते हैं, किंतु छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में यह शीघ्र और अधिक घातक रूप ले सकता है। रोगी के ठीक होने के बाद भी यह रोग पुनः हो सकता है। वर्षा ऋतु में या वर्षा के बाद जब घरों, गलियों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है, तब मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है और संक्रमण का प्रसार बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्वच्छता और जलभराव रोकना मलेरिया नियंत्रण का अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। यह रोग मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, अमेरिका तथा अन्य उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होती है। मलेरिया गरीब क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, सुरक्षित आवास और रोकथाम के संसाधनों की कमी होती है।

क्यों अचानक ईरान के इशारों पर नाचने लगे ट्रंप?

अभिनय आकाश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम यानी सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले सीज फायर की जो समय सीमा दी गई थी वो आज यानी 22 अप्रैल को खत्म हो रही थी। उससे पहले ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने की जानकारी सार्वजनिक कर दी। एकदम वैसे जैसे फोन का टॉक टाइम खत्म होने से पहले ठीक पहले रिचार्ज करा लिया जाता है। यह टैक्टिकल सीज फायर एक्सटेंशन ट्रंप ने किसके कहने पर किया है यह भी बताते हैं। भारत के पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान जिसे आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। फिल वक्त वही पाकिस्तान पीस मैसेंजर ऑफ द ईयर बना हुआ है। ट्रंप का कहना है कि इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर उन्होंने सीजफायर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर ईरान ने अपनी शर्तों पर ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। आज हम पूरे मामले का एमआरआई स्कैन करेंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार बुरी तरह बिखरी हुई है। यह कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर हमने ईरान पर हमला फिलहाल टाल दिया है। जब तक ईरान के नेता एकमख होकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाते तब तक हमारा ब्लॉकेट जारी रहेगा। सेना पूरी तरह तैयार है। हम सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं। सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। यानी सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं किया है। उन्होंने अमेरिकी सेना को साफ आदेश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकेबंदी को जारी रखा जाए। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली सामने आती है जो ट्रंप पहले मैक्सिमम प्रेशर की नीति चला रहे थे। हालांकि ट्रंप के इस नए दांव को शांति की पहल तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। देखिए सीज फायर बढ़ाया है लेकिन ब्लॉकेट जारी है। मतलब ईरान पर आर्थिक दबाव और सैन्य तैयारियां दोनों बरकरार हैं। शांति की असली पहल में दोनों तरफ से कुछ रियायतें दी जाती हैं। यहां सिर्फ हमला टाला गया है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की सरकार को सीरियसली फ्रैक्चरर्ड यानी गंभीर रूप से विभाजित या बिखरी हुई भी बताया है। जानकार इसे रणनीतिक दबाव का हिस्सा बता रहे हैं।

दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे बातचीत का एक नया दौर आयोजित करेंगे। पाकिस्तान के नेतृत्व वाले मध्यस्थों को इस बात की पुष्टि मिली कि शीर्ष वार्ताकार - वैंस और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर ग़ालिबफ़ अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन मंगलवार देर रात, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत में शामिल होने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रवक्ता इस्माइल बघाएई ने सरकारी टीवी को बताया कि निर्णय न ले पाने का कारण अमेरिकियों की ओर से मिले विरोधाभासी संदेश और अस्वीकार्य कार्य थे, विशेष रूप से ईरान की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी। इस बीच, वैंस ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा रद्द कर दी, जबकि पाकिस्तानी नेता बातचीत को बचाने की कोशिश में तेज़ी से जुट गए। 0000 तरूझ की समय सीमा नज़दीक आते ही, ट्रंप ने घोषणा की कि संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह कदम पाकिस्तान के अनुरोध पर उठाया है और इस मामले में किसी निर्णय पर न पहुँच पाने के लिए उन्होंने ईरान के गंभीर रूप से बिखरे हुए नेतृत्व को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनसे तब तक इंतज़ार करने को कहा था, जब तक कि ईरान के नेता कोई एकमत प्रस्ताव लेकर नहीं आ जाते। फिर भी, उन्होंने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। भले ही पाकिस्तान किसी बैठक का इंतज़ाम कर ले, फिर भी स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के भविष्य, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और नाकेबंदी को लेकर गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस सप्ताहांत ईरान ने स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी एक ईरानी जहाज़ पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, जिसने स्ट्रेट में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से बचकर निकलने की कोशिश की थी - जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रांची ने भी नौसैनिक घेराबंदी को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। यानी ट्रंप अपनी डील मेकर इमेज बचाने की कोशिश में लगे हैं। नया नवेला शांतिदूत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में अपनी अहमियत बढ़ा रहा है और ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं है।

अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू किया, जो छह हफ़्ते तक चला। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ गईं और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई। ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच मौजूदा संघर्ष-विराम 8 अप्रैल को शुरू हुआ। इससे पहले ट्रंप ने कई समय-सीमाएं तय की थीं, जिनसे एक समय तो ईरान की सभ्यता पर ही खतरा मंडराने लगा था। पिछले शुक्रवार को, इज़राइल और लेबनान में मौजूद ईरान-समर्थित हिज़्बुल्लाह आतंकवादी समूह के बीच भी एक संघर्ष-विराम लागू हुआ। ये दोनों संघर्ष-विराम मोटे तौर पर कायम रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का एक पिछला दौर पाकिस्तान में 11 अप्रैल से शुरू होकर अगले दिन तड़के तक चला। वेंस ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच हुई अब तक की सबसे उच्च-स्तरीय बातचीत में हिस्सा लिया, जो बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई। इस सप्ताहांत से इस्लामाबाद के अधिकारियों ने वैसी ही तैयारियां की हैं जैसी पहले दौर की बातचीत के दौरान की गई थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि बातचीत का एक और दौर जल्द ही शुरू होने वाला है।

होरमुज़ जलडमरूमध्य, जो फ़ारसी खाड़ी का एक संकरा मुहाना है और जिससे दुनिया की 20त्न प्राकृतिक गैस और तेल गुज़रता है, जलमार्ग में ईरानी हमलों के कारण लगभग बंद पड़ा है। इसमें शनिवार को हुए कुछ हमले भी शामिल हैं। इस बात का भी डर है कि ईरान ने जलडमरूमध्य के उस हिस्से में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसका इस्तेमाल शांति काल में जहाज़ों के गुज़रने के लिए किया जाता था। युद्ध शुरू होने के बाद से, ख़बरों के मुताबिक, ईरान जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने की अनुमति देने के बदले प्रति जहाज़ 20 लाख डॉलर तक की रक़म वसूल रहा है। जलडमरूमध्य को फिर से खोलना बातचीत का एक अहम मुद्दा बना हुआ है और वॉशिंगटन के ख़िलाफ़ तेहरान का सबसे मज़बूत दाँव है; ख़ास तौर पर ऐसे समय में, जब दुनिया भर के देशों ने ऊर्जा की राशनिंग शुरू कर दी है और जेट ईंधन की कमी की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाज़ों को रोकना शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने इस सप्ताहांत एक ईरानी कंटेनर जहाज़ पर हमला किया, जिसने अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी; इस दौरान अमेरिकी मरीन हेलीकॉप्टरों से रस्सी के सहारे उस जहाज़ पर उतरे थे। ईरान ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे समुद्री डकैती और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन बताया है।

ईरान का सारा अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम देश के भीतर ही मौजूद है; संभवतः यह उन संवर्धन स्थलों के मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिन पर पिछले जून में चले 12-दिवसीय युद्ध के दौरान अमेरिका ने बमबारी की थी।

आज का इतिहास

- 1867 जापान की राजधानी टोक्यो में विदेशी व्यापार की अनुमति दी गई।
- 1891 अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की।
- 1901 न्यूयॉर्क ऑटोमोबाइल, लाइसेंस प्लेटों का पहला अमेरिकी राज्य बना।
- 1905 दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मताधिकार मिला।
- 1915 प्रथम विश्व युद्ध-ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड आर्मी कोर ने अंजैक कोव को उतारा, जबकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों ने केप हेल्स में ओटोमन साम्राज्य में गैलीपोली प्रायद्वीप के मित्र देशों के आक्रमण के लिए उतरा।
- 1925 पॉल वोन हिंडनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गये।
- 1936 ओगडेन की लड़ाई में इटली की जीत हुई।
- 1945 जर्मन फ़ौज उत्तरी फ़िनलैंड से पीछे हट गई, लैपलैंड युद्ध को बंद कर दिया।
- 1950 कम्युनिस्ट जासूस जूडिथ कॉपल का परीक्षण न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ।
- 1953 आणविक जीवविज्ञानी जैम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा न्यूक्लिक एसिड की आणविक संरचना को पहली बार वैज्ञानिक हेलिकॉप्टर में प्रकाशित किया गया था, जिसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरो डीएनए की खोज का वर्णन था।
- 1954 बेल लैब्स ने न्यूयार्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की।
- 1957 सोडियम परमाणु रिएक्टर पहली बार प्रायोगिक तौर पर संचालित किया गया।
- 1964 जेम्स बाल्डविन के ब्लूज़ फॉर मिस्टर चार्ली, का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर में हुआ।
- 1965 1 सोवियत संचार उपग्रह का प्रक्षेपण।
- 1981 जापान के सुरूगा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मरम्मत कार्य के दौरान 100 से अधिक मजदूर परमाणु विकिरण का शिकार हो गये।
- 1986 स्वास्तिलैंड के राजा मस्वाती तृतीय को ताज पहनाया गया, जो उनके पिता सोभूजा द्वितीय के उत्तराधिकारी थे।
- 1989 न्यूयॉर्क में एक ड्रैग रेस आयोजित की गई थी। इस ड्रैग रेस में ल्यूक टायसन को टिकट में तेजी मिली।
- 1990 शटल की खोज हुई। इसके द्वारा एक शटल स्पेस सेटल को कक्षा में रखा गया।
- 1990 वायलेट चामोरो ने अमेरिका में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, जो अपने आप में चुनी हुई महिला थीं।

वैश्विक औसत से बहुत दूर है सत्ता में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का बिल गिरने के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफी मांगी है तो दूसरी और विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताई है। हांलाकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विरोध सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर यह अलग बहस का विषय हो सकता है। पर एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामलें में हम दुनिया के देशों से अभी काफी पीछे चल रहे हैं। दुनिया के 190 देशों के आंकड़ों का विष्लेषण करे तो हमारे देश का स्थान 147 वां आता है। दुनिया के देशों में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 महिला राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं वहीं इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनावों में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 19 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या अन्य प्रदेशों में लखपति दीदी या इसी तरह के नाम से मिलती जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी

और करने की रही है, यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहे या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक महिलाओं की बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रौचक बात यह है कि 2009 की 15 वीं लोकसभा के पहले तक तो हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15 वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हांलाकि 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपातकाल के बाद की स्थितियां थी। 18 वीं लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम है। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही।

जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्य सभा में टीएमसी दल की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस की भागीदारी 14.3 प्रतिशत और बीजेपी की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य है। त्रिपुरा में 15 प्रतिशत महिला सदस्य है। बाकी देश के अन्य राज्यों में 15 प्रतिशत महिलाएं भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। नागालैंड देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कम महिला सदस्य है। कर्नाटक जैसे राज्य में भी पांच प्रतिशत से कम महिला विधानसभा सदस्य है।

खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है। जहां महिलाओं की सीटे आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। आज सरपंच पति या प्रधान पति वाली बात भी नहीं रही है। पिछले चुनाव परिणाम भी यह साफ कर चुके हैं कि आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेती है। यही कारण है कि सरकार बनने और बनाने में महिलाओं मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। आने वाले समय में इसमें और अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में एक बात साफ हो जानी चाहिए कि बिना आरक्षित सीटों के विधानसभाओं या संसद में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ने की कल्पना करना बेमानी होगी। यह तो संवैधानिक बाध्यता से ही संभव हो पाएगा। यह सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा। यदि महिलाओं की सत्ता में सहभागिता बढ़ानी है तो महिला सीटों का आरक्षण करना ही होगा। यह अवश्य है कि आरक्षण की सीमा आपसी समन्वय व विचार विमर्श से सर्वसम्मति से तय होता है तो यह बेहतर लोकतांत्रिक परंपरा होगी। राजनीतिक दलों को आपसी आग्रह दुराग्रहों से हटकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों को भी इस दिशा में देश में माहौल बनाना चाहिए। यह साफ है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं की हिस्सेदारी तय होनी ही चाहिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: नाम, प्रक्रिया और राजनीति के बीच की सच्चाई

मुकेश मिश्रा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश में इन दिनों व्यापक चर्चा और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई अलग से पारित कानून नहीं है, बल्कि यह वह लोकप्रिय नाम है जो सरकार ने संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 को दिया था। यह विधेयक संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित हुआ और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे आधिकारिक रूप से संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संवैधानिक और कानूनी दस्तावेजों में इसी नाम का उपयोग होता है, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक राजनीतिक या लोकप्रिय संज्ञा है, जिसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है।

16 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी कानून को प्रभावी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई असामान्यता नहीं है और यह पूरी तरह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसी बीच, 16 और 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। इस संशोधन का उद्देश्य 2023 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन से जुड़े मुद्दों में बदलाव करना था। हालांकि, यह विधेयक लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर सका और पारित नहीं हो पाया।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में उसमें संशोधन लाने का प्रयास करना विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे मूल कानून की वैधता या अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2023 का अधिनियम आज भी पूरी तरह अस्तित्व में है और प्रभावी है।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आगामी चुनावों, विशेष रूप से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। वहीं, सरकार ने विपक्ष पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए देशभर में जनमत तैयार करने का प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष पर लगाए गए आरोपों ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। साथ ही, चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामला अब न्यायिक दायरे में भी पहुंच गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।

निष्कर्षत:, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण इसके नाम और प्रक्रिया को लेकर अपर्याप्त समझ है। यह आवश्यक है कि संवैधानिक तथ्यों और विधायी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझा जाए, ताकि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग हटकर वास्तविकता को पहचाना जा सके।

बंगाल में सत्ता विरोधी लहर का फायदा क्या उठा पाएगी भाजपा?

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सवाल सीधा है कि क्या सत्ताविरोधी माहौल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने पक्ष में मोड़ पाएगी? या फिर ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर कायम रहेगा? वैसे राज्य में चुनावी हवा भले ही बदलाव की सुगबुगाहट दिखा रही हो, लेकिन जमीन पर हालात इतने सरल नहीं हैं। देखा जाये तो इस बार के चुनावों में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां, केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और संगठन की आक्रामक रणनीति यह संकेत देती है कि पार्टी किसी भी कीमत पर बंगाल में सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी अपनी पकड़ ढीली पड़ने देने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी, जो लंबे समय से राज्य की राजनीति का केंद्र रही हैं, अब भी अपने जनाधार और कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे मैदान में डटी हुई हैं।

उधर, भाजपा के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है 'एंटी-इंकम्बेंसी' यानी सत्ता के खिलाफ बढ़ती नाराज़गी। टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और कानून-व्यवस्था के सवालों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। भर्ती घोटाले, स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की दबंगई और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे भाजपा के चुनावी एजेंडे के केंद्र में हैं। पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार वोट उसी दिशा में जाएगा।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। ममता बनर्जी ने बीते वर्षों में महिला मतदाताओं, ग्रामीण गरीबों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया है, जबकि अन्य सामाजिक योजनाओं ने गरीब तबकों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यही कारण है कि भाजपा के आक्रामक अभियान के बावजूद टीएमसी का आधार पूरी तरह हिलता नजर नहीं आता।

इसके अलावा, भाजपा की रणनीति में एक अहम

किरदार हैं शुभेन्दु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे और अब उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं। शुभेन्दु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी और इस बार ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं। शुभेन्दु अधिकारी राज्य में भाजपा का चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि, उनका प्रभाव सीमित इलाकों तक ही केंद्रित माना जाता है, और पूरे बंगाल में एक व्यापक लहर खड़ी करना उनके लिए आसान नहीं है।

हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में टर्निंग प्वाइंट साबित हुए थे। पार्टी ने उस चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल करते हुए खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। उसी प्रदर्शन के आधार पर भाजपा को उम्मीद थी कि वह विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंच सकती है। लेकिन बाद के चुनावी अनुभवों ने यह भी दिखाया कि लोकसभा और विधानसभा की राजनीति में मतदाताओं का व्यवहार अलग हो सकता है।

एक और चुनौती भाजपा के सामने सांस्कृतिक और भाषाई असंतुलन की है। बंगाल की अपनी विशिष्ट पहचान है, और यहां बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा अक्सर उभरता रहता है। भाजपा के कई नेताओं के बयान और रणनीतियां कभी-कभी स्थानीय संवेदनशीलताओं से मेल नहीं खातीं, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। टीएमसी इस मुद्दे को भुनाने में माहिर रही है और खुद को 'बंगाल की असली आवाज' के रूप में पेश करती है।

इसके अलावा, मतदाताओं के एक हिस्से में यह धारणा भी है कि भाजपा की राजनीति अत्यधिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। धार्मिक और पहचान की राजनीति का असर भले कुछ क्षेत्रों में दिखता हो, लेकिन पूरे राज्य में यह रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर सवाल बना हुआ है। बंगाल का सामाजिक ताना-बाना जटिल है, और यहां की राजनीति सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं टिकती।

दूसरी ओर, टीएमसी के खिलाफ असंतोष को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ग्रामीण इलाकों में विकास की असमानता, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दे लोगों के बीच चर्चा में हैं। भाजपा इन्हीं सवालों को उठाकर खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है।

वैसे बंगाल की चुनावी लड़ाई सिर्फ आंकड़ों और नारों की नहीं है, बल्कि भावनाओं, पहचान और भरोसे की भी है। भाजपा के पास आक्रामक अभियान और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन है, लेकिन टीएमसी के पास जमीनी नेटवर्क और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है। इसलिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि सत्ताविरोधी लहर किसके पक्ष में जाएगी। भाजपा के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी क्योंकि उसे नाराज़गी को वोट में बदलना होगा। वहीं ममता बनर्जी के लिए यह अपनी विश्वसनीयता और जनसंपर्क की सबसे बड़ी परीक्षा है।

बहरहाल, इस चुनाव का नतीजा सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता में पुनरावृत्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि बंगाल की राजनीति आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल, मैदान सजा है, दांव बड़े हैं और फैसला पूरी तरह जनता के हाथ में है, जो इस बार सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि राजनीतिक कथा का अगला अध्याय लिखने जा रही है।

भारत-चीन संबंध में सुधार रणनीतिक है

आनंद कुमार

भारत-चीन संबंधों में हाल के महीनों में जो नरमी दिख रही है, वह दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास में किसी बुनियादी बदलाव का परिणाम कम और तेजी से विखंडित होती वैश्विक व्यवस्था के दबावों का नतीजा अधिक है। पिछले एक दशक तक दोनों को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता रहा, जिनके बीच सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और अलग-अलग रणनीतिक झुकाव जैसे गहरे मतभेद मौजूद थे। वर्ष 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह धारणा और मजबूत ही हुई कि दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक तनावपूर्ण बने रहेंगे। पर 2025 के बाद के घटनाक्रम बताते हैं कि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। यह बदलाव इसलिए नहीं है कि उनके मूल विवाद सुलझ गये हैं, बल्कि इसलिए है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने सहयोग के लिए एक सीमित, लेकिन महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर दिया है।

जिस अमेरिका को भारत लंबे समय तक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता रहा, ट्रंप के नेतृत्व में वह अधिक लेन-देन आधारित और अनिश्चित रुख अपनाता नजर आ रहा है। भारत और चीन पर लगाये गये टैरिफ, खासकर भारतीय निर्यात पर कड़े शुल्क यह दिखाते हैं कि वैश्विक आर्थिक संबंध कितने अस्थिर हैं। चीन के प्रति अमेरिकी नीति में भी उतार-चढ़ाव दिखता है, जहां एक ओर दबाव बनाया जाता है, दूसरी ओर कुछ मामलों में समझौते की गुंजाइश भी रखी जाती है। इस असमान व्यवहार ने भारत को सोचने पर मजबूर किया है कि अमेरिका पर निर्भर रहना रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इसी परिदृश्य में चीन ने भी तेजी से कूटनीतिक अवसर को भुनाने की कोशिश की है।

चीनी नेताओं के बयान इस पर जोर देते हैं कि भारत और चीन के साझा हित उनके मतभेदों से कहीं अधिक हैं। चीन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भारत को अमेरिकी नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक ढांचे, खासकर क्वाड जैसे मंचों के साथ अपने जुड़ाव को संतुलित रखते हुए बीजिंग के साथ सहयोग के रास्ते खुले रखने चाहिए। कुछ ठोस कदम भी इस दिशा में उठाये गये हैं। भारत द्वारा सीमित रूप से चीनी निवेश के लिए नियमों में ढील देना संकेत है कि नयी दिल्ली आर्थिक वास्तविकताओं को समझते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और पूंजीगत वस्तुओं में चीन की भूमिका की अनदेखी करना भारत के लिए संभव नहीं है,

खासकर तब, जब वह अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है। इसी तरह, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों का फिर से शुरू होना, पर्यटक वीजा की बहाली और कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनरारंभ दर्शाता है कि दोनों पक्ष संबंधों को सामान्य बनाने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं।

दोनों देश हाल के भू-राजनीतिक झटकों से उत्पन्न समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। होर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता ने दोनों की बाहरी निर्भरता उजागर की है। चीन के लिए खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना लंबे समय से रणनीतिक प्राथमिकता रही है, जबकि भारत के लिए महंगा तेल महंगाई, मुद्रा दबाव और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। ऐसे में, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं या भुगतान संबंधी समस्याएं सामने आती हैं, तब भारत को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन साझा चिंताओं ने दोनों देशों को सीमित सहयोग की ओर प्रेरित किया है। भारत और चीन समझते हैं कि विखंडित वैश्विक व्यवस्था उनके आर्थिक हितों के लिए खतरा है। इसीलिए सीमित स्तर पर सहयोग करना उनके लिए व्यावहारिक बनता जा रहा है।

चीन के लिए भारत के साथ संतुलित संबंध बनाये रखना इस बात की गारंटी देता है कि एशिया में उसके खिलाफ एकजुट मोर्चा न बने, जबकि भारत के लिए यह अमेरिका के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाये रखने का एक साधन है। हालांकि, इस नरमी को स्थायी सुधार के रूप में देखना गलत होगा। दोनों देशों के बीच अविश्वास के मूल कारण अब भी मौजूद हैं। सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की आशंका बनी रहती है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ चीन की घनिष्ठता, जिसमें सैन्य और परमाणु सहयोग शामिल है, भारत के लिए चिंता का विषय है। जल संसाधनों, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़े मुद्दे भी आपसी अविश्वास बढ़ाते हैं।

बहुपक्षीय मंचों पर भी चीन का रवैया कई बार भारत के हितों के अनुरूप नहीं होता। दोनों देशों के बीच शक्ति का असंतुलन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। चीन की आर्थिक और तकनीकी क्षमता भारत से अधिक है, जिससे उसे वैश्विक मंचों पर अधिक प्रभाव मिलता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन और भारत के साथ व्यवहार करने का तरीका अलग-अलग होता है। यह स्थिति भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाये रखते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होती है। नयी दिल्ली ने अब तक इस स्थिति का संतुलित तरीके से सामना किया है। उसने अमेरिका और अन्य साझेदार देशों के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं किया है, लेकिन साथ ही, चीन के साथ संवाद और सहयोग के रास्ते भी खुले रखे हैं। यह भारत की पारंपरिक रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के अनुरूप है, जिसमें किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए बहुआयामी संबंध बनाये जाते हैं। लेकिन इस नीति को सफल बनाने के लिए भारत को अपनी घरेलू क्षमताओं को भी मजबूत करना होगा, चाहे वह विनिर्माण हो, प्रौद्योगिकी हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा।

इन दिनों भारत-चीन संबंधों में जो सुधार दिख रहा है, वह अंततः एक रणनीतिक समायोजन है, न कि स्थायी समाधान। दोनों देश बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अपने-अपने विकल्प तलाश रहे हैं। सहयोग और प्रतिस्पर्धा का यह मिश्रण भविष्य में भी बना रहेगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि दोनों देश अपने मतभेदों को कितनी समझदारी से संभालते हैं और किस हद तक अपने साझा हितों को प्राथमिकता देते हैं। अभी यह कहना उचित होगा कि भारत और चीन पारंपरिक अर्थों में साझेदार नहीं बन रहे, बल्कि अनिश्चित और बदलती विश्व व्यवस्था में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं। यह एक सावधानीपूर्ण और सीमित सहयोग है, जो परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। जब तक मूल विवादों का समाधान नहीं होता, तब तक यह नरमी नाजुक ही बनी रहेगी और दोनों देशों को हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा।

अविश्वास की आग में झुलस रहे मुनीर

विकास मिश्रा

दुनिया भर में इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग में खुद को मध्यस्थ बना कर बड़ी कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की बहुत तारीफ हो रही थी। ट्रम्प तो अब भी तारीफ के पुल बांध रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि मुनीर अविश्वास की आग में झुलस रहे हैं। ईरान ने उनकी खुली आलोचना की है तो दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए उन्हें संदेह की गहरी नजर से देख रही है। इस संदेह की वजह भी है। जंग खत्म करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत के पहले ट्रम्प ने जब सीजफायर की घोषणा की तो साथ में यह भी जोड़ा कि यह कदम वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के आग्रह पर उठा रहे हैं। दोनों फूले नहीं समाए लेकिन इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने जो तेवर दिखाए, उसने सबको चौंका दिया। वहां का सरकारी मीडिया वही खबर सामने रखता है जो सरकार का पक्ष होता है। तो ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान 'डबल गेम' खेल रहा है। जनरल आसिम मुनीर वास्तव में ईरानी नेताओं से निजी संपर्क होने का ढोंग कर रहे हैं। ईरान के हकों का दिखावा कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वे अमेरिकी हितों के लिए काम कर रहे हैं। निष्पक्षता केवल दिखावा है। ईरानी मीडिया ने तो मुनीर को अमेरिका का पोस्टमैन तक कह दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए यह गहरा धक्का है। यदि ईरान उसकी बात नहीं सुनता है तो फिर उसकी जरूरत क्या रह जाएगी? दरअसल मध्यस्थता के लिए पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का चयन अमेरिका ने इसलिए किया था कि मुनीर के संबंध ईरान के बड़े नेताओं से रहे हैं। 2016-17 के दौरान जब वे पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख थे तो उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपने संबंध विकसित किए। उनके संबंध कमांडर कासिम सुलेमानी और कमांडर हुसैन सलामी के साथ भी बड़े गहरे थे। अमेरिका को भरोसा था कि उसके दूत के रूप में मुनीर अच्छा काम कर सकते हैं। मुनीर ने इस भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश भी की है। अभी अप्रैल में ही मुनीर ने ईरान का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और खातम-अल-अनबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही के साथ बातचीत की। वे अमेरिका का संदेश लेकर पहुंचे थे लेकिन उनकी दाल गली नहीं। जिस दिन वे तेहरान पहुंचे थे, उसी दिन वहां के एक अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका का संदेश देने तेहरान आए हैं। अब ईरान का सरकारी मीडिया कह रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्हें ईरानी नेताओं द्वारा ईरानी पक्ष का एक मसौदा सौंपा गया था और कहा गया था कि यह मसौदा वे अमेरिका तक पहुंचा दें लेकिन आज तक मुनीर ने ईरान को नहीं बताया कि उस मसौदे का क्या हुआ? मुनीर ने इस चाहत का इजहार किया कि अमेरिका की पंद्रह नई मांगों को ईरान स्वीकार कर ले। इससे स्पष्ट है कि मुनीर के लिए ईरान का पक्ष कोई मायने नहीं रखता। वे तो बस अमेरिका की मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान इसे स्वीकार नहीं करेगा। सरकारी मीडिया पर कई विश्लेषकों ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान के क्षेत्रीय प्रभुत्व को कम करने का काम पाकिस्तान कर रहा है। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। संभव है कि यह बात सही हो क्योंकि पिछले सप्ताह ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को करीब 9400 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि इसे कर्ज कहा गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान को ऐसे ही खरीदा जाता है! अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वह ईरान को बातचीत की मेज पर भी नहीं ला पा रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने साफ कह दिया कि ईरान को धमकी देकर नहीं झुकाया जा सकता। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की लेकिन यह माना जा रहा है कि इस्लामाबाद में बैठे राजदूत का इस तरह दहाड़ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है! दरअसल पाकिस्तान की पूरी चालाकी को ईरान ने समझ लिया है। मगर पाकिस्तान और खासकर आसिम मुनीर की समस्या यहीं खत्म नहीं हुई है! डोनाल्ड ट्रम्प भले ही उनकी तारीफ करते नहीं थकते मगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की राय मुनीर के बारे में बिल्कुल अलग है। अब यह बात लगातार सामने आ रही है कि सीआईए के अधिकारी ट्रम्प तक यह बात पहुंचाते रहे हैं कि मुनीर पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

जांघों में खुजली क्यों होती है?

गर्मियों में पसीना बढ़ने के साथ शरीर में खुजली की समस्या आम हो जाती है। खासकर जांघों के बीच होने वाली खुजली कई बार असहज स्थिति पैदा कर देती है। अक्सर लोग इसे साधारण समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में यह शरीर के अंदर की कमी या इंफेक्शन का संकेत भी हो सकती है। इसलिए इसका सही कारण समझना बेहद जरूरी है।

जांघों में खुजली के मुख्य कारण

जांघों में खुजली कई वजहों से हो सकती है। सबसे आम कारण ज्यादा पसीना आना है, जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है और बैक्टीरिया या फंगस पनपने लगते हैं। इसके अलावा फंगल इंफेक्शन भी एक बड़ी वजह है, जो खासकर गर्म और नम जगहों पर जल्दी फैलता है। टाइट कपड़े पहनने से त्वचा पर रगड़ होती है, जिससे जलन और खुजली बढ़ जाती है। अगर अंडरवियर समय पर नहीं बदला जाए या साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो भी यह समस्या बढ़ सकती है। साथ ही, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी खुजली का कारण बन सकती है।

किस विटामिन की कमी से होती है खुजली?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जांघों में खुजली का एक अहम कारण विटामिन क्र की कमी हो सकता है। खासतौर पर विटामिन क्र2, क्र6 और क्र12 की कमी से त्वचा ड्राई और संवेदनशील हो जाती है। जब त्वचा में नमी कम हो जाती है, तो उसमें खुजली, जलन और रूखापन बढ़ने लगता है। इसलिए शरीर में इन विटामिन्स का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि त्वचा स्वस्थ बनी रहे।

आयुर्वेद के अनुसार कारण

आयुर्वेद में खुजली को 'कंडू' कहा जाता है। इसके अनुसार यह समस्या शरीर में पित्त और कफ दोष के असंतुलन की वजह से होती है। जब हम ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या मीठा खाना खाते हैं, तो यह असंतुलन और बढ़ जाता है। इसका असर त्वचा पर दिखने लगता है और खुजली की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए संतुलित और हल्का भोजन करना फायदेमंद होता है।

खुजली से राहत पाने के आसान उपाय

खुजली से राहत पाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। नहाने के पानी में नीम के पत्ते उबालकर मिलाने से त्वचा के बैक्टीरिया खत्म होते हैं और खुजली में आराम मिलता है। सही खानपान भी बहुत जरूरी है। डाइट में विटामिन से भरपूर फल और हरी सब्जियां शामिल करें, ताकि शरीर की इम्युनिटी मजबूत रहे। नारियल तेल और एलोवेरा जेल को मिलाकर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और खुजली कम होती है। इसके साथ ही हमेशा साफ और ढीले कपड़े पहनें, रोज अंडरवियर बदलें और शरीर को सूखा रखने की कोशिश करें, ताकि इंफेक्शन का खतरा कम हो सके।

कब डॉक्टर से सलाह लें?

अगर खुजली लंबे समय तक बनी रहती है या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना जरूरी है, ताकि सही कारण का पता लगाकर समय पर इलाज किया जा सके।

हर दिन तिल खाने से मिलेंगे ये फायदे, दांत और मसूड़े भी रहेंगे मजबूत

आयुर्वेद में तिल को हमेशा से ही एक 'पोषण का खजाना' माना गया है। ये छोटे-छोटे बीज दिखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन इनके अंदर सेहत के लिए कई बड़े फायदे छिपे होते हैं। खासकर दांत, मसूड़े और हड्डियों की मजबूती के लिए तिल बेहद उपयोगी माना जाता है।

दांत और मसूड़ों को बनाता है मजबूत

तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो दांतों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। नियमित रूप से तिल का सेवन करने से दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं और मसूड़ों की कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद फॉस्फोरस दांतों की संरचना को मजबूत बनाता है, जिससे दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं।

हड्डियों के लिए भी फायदेमंद

तिल सिर्फ दांतों ही नहीं, बल्कि हड्डियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कमजोरी को कम करते हैं।

खून की कमी और इम्युनिटी में मददगार

वहीं जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को बढ़ाता है, जिससे शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है तिल में आयरन भी पाया जाता है, जो शरीर में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने में मदद करता है।

दिल की सेहत के लिए भी अच्छा

तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इससे दिल की सेहत बेहतर रहती है और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।

पाचन तंत्र को करता है मजबूत

तिल में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है और पेट को साफ रखने में सहायक होता है।

त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी

तिल के एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को निखार देने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि कई स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी तिल का उपयोग किया जाता है। छोटे दिखने वाले तिल के बीज वास्तव में सेहत का बड़ा खजाना हैं। इन्हें संतुलित मात्रा में अपने दैनिक आहार में शामिल करके शरीर को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं।

बार-बार जम्हाई आना हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जम्हाई आना एक आम बात मानी जाती है। अक्सर लोग इसे नींद की कमी, थकान या बोरियत से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यही साधारण सी लगने वाली जम्हाई शरीर के अंदर छिपी किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है? अगर आपको बिना किसी स्पष्ट वजह के बार-बार जम्हाई आने लगे, तो यह सिर्फ थकान नहीं बल्कि शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे कारण और कब आपको सतर्क हो जाना चाहिए।

दिमाग से जुड़ी समस्याओं का संकेत

लगातार और अनियंत्रित जम्हाई कई बार न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से जुड़ी बीमारियों से जुड़ी हो सकती है। यह स्थिति मिर्गी, आघात या ब्रेन में चोट जैसी समस्याओं से संबंधित हो सकती है। कुछ मामलों में यह फ्रंटल लोब सीजर का हिस्सा भी हो सकती है, जिसमें दिमाग का एक हिस्सा असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है। ऐसे में शरीर बार-बार जम्हाई लेने लगता है क्योंकि दिमाग के सामान्य कार्य प्रभावित होने लगते हैं।

ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी

जम्हाई का संबंध सिर्फ दिमाग से ही नहीं, बल्कि शरीर के स्वतंत्र तंत्रिका प्रणाली से भी होता है। यह सिस्टम दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और पाचन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब इसमें असंतुलन आता है, तो बार-बार जम्हाई आ सकती है। रिसर्च के अनुसार, जम्हाई के दौरान शरीर का पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है।

दिमाग के तापमान से जुड़ा संबंध

कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जम्हाई का संबंध दिमाग के तापमान को नियंत्रित करने से भी होता है। जब दिमाग गर्म होने लगता है, तो जम्हाई के जरिए ठंडी हवा अंदर जाती है, जिससे दिमाग को ठंडा करने में मदद मिलती है। हालांकि, यह सिद्धांत अभी भी शोध का विषय है।

कब सतर्क होना जरूरी है?

हर बार जम्हाई आना किसी बीमारी का संकेत नहीं होता।

अक्सर इसके पीछे ये सामान्य कारण हो सकते हैं

नींद की कमी होना।

ज्यादा काम या थकान

बोरियत या मानसिक थकावट

लेकिन अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत सावधान हो जाएं

बिना वजह बार-बार जम्हाई आना

चक्कर आना

कमजोरी महसूस होना

ध्यान लगाने में परेशानी

सोचने-समझने में बदलाव

ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

क्यों जरूरी है समय पर जांच?

अगर जम्हाई किसी गंभीर समस्या का संकेत है, तो समय रहते जांच और इलाज बहुत जरूरी हो जाता है। शुरुआत में ही ध्यान देने से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सकता है। जम्हाई आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब यह बार-बार और बिना कारण होने लगे, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। शरीर अक्सर छोटे-छोटे संकेतों के जरिए हमें बड़ी समस्याओं के बारे में पहले ही चेतावनी देता है। इसलिए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और किसी भी असामान्य लक्षण को समय रहते समझकर सही कदम उठाएं।

गले के कैंसर की शुरुआत किन वजहों से होती है?

5 कारण जरूर जानें

गले का कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो धीरे-धीरे विकसित होती है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य गले की समस्या जैसे लगते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर समय रहते इसके संकेत पहचान लिए जाएं, तो इलाज आसान हो सकता है और बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

गले में कैंसर कैसे शुरू होता है?

गले का कैंसर तब शुरू होता है जब गले की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं। यह स्थिति लंबे समय तक गले में जलन, संक्रमण या लगातार नुकसान की वजह से विकसित हो सकती है। शुरुआत में यह समस्या साधारण इंफेक्शन जैसी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकती है।

लगातार गले में खराश रहना

अगर गले में खराश या दर्द 2-3 हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर लोग इसे सामान्य सर्दी-खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह शुरुआती संकेत हो सकता है।

आवाज में बदलाव आना

गले के कैंसर की शुरुआत में आवाज भारी या बदल जाती है। यह बदलाव लंबे समय तक बना रहता है और दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता। अगर आवाज लगातार बदल रही हो, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

गर्दन या गले में गांठ बनना

गले या गर्दन में किसी भी तरह की सूजन या गांठ का बनना चिंता का विषय हो सकता है। अगर यह गांठ समय के साथ कम न हो और लगातार बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

खांसी में खून आना

अगर खांसी के दौरान खून आने लगे, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। गले में दर्द के साथ खून आना सामान्य बात नहीं है और तुरंत मेडिकल जांच की जरूरत होती है।

गले में लगातार जलन या असहजता

गले में लंबे समय तक जलन, खिंचाव या कुछ अटका हुआ महसूस होना भी शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकता है। यह समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गले का कैंसर धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, लेकिन इसके शुरुआती संकेतों को पहचानकर समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है। लगातार गले में परेशानी, आवाज में बदलाव या गांठ जैसे लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ से जांच करवाएं।

सिगरेट की कश कहीं ले न ले आपकी जान, एक्सीडेंट और हार्ट अटैक से ज्यादा स्मोकिंग से मर रहे लोग

धूम्रपान वास्तव में बहुत हानिकारक है। यह बात ज्यादातर लोग जानते हैं। यहां तक ??कि धूम्रपान करने वाले भी मानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह कितना नुकसानदायक है। हर साल धूम्रपान से मरने वालों की संख्या शराब, मादक पदार्थों के सेवन, कार दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और हत्याओं से होने वाली कुल मौतों की संख्या से कहीं अधिक है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार, इसके सेवन से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। इसके बावजूद, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और खैनी जैसी आदतें कई देशों में आम बनी हुई हैं।

सिगरेट क्यों है इतना खतरनाक-सिगरेट में निकोटिन और कई जहरीले रसायन होते हैं जो शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। यह धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। सिगरेट के सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और अन्य कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यह ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसी गंभीर सांस की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मुंह में संक्रमण, दांतों का पीला पड़ना और मसूड़ों की बीमारी भी तंबाकू का बड़ा असर है।

पैसिव स्मोकिंग भी है खतरनाक - सिर्फ सिगरेट पीने वाला ही नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी सेकेंड हैंड स्मोक के कारण प्रभावित होते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। सिगरेट छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन संभव जरूर है। इसके लिए काउंसलिंग और मेडिकल सहायता, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, परिवार और समाज का समर्थन बहुत मददगार हो सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

आतंकवादी टिप्पणी पर खरगे ने चुनाव आयोग दिया जवाब

नईदिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी आतंकवादी टिप्पणी के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि हमने पहले ही जवाब दे दिया है; यह अखबार में छप चुका है। यह घटना कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को लिखे पत्र के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की इस बात के लिए आलोचना की थी कि खरगे को आरोपों का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया है। पार्टी ने विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। ईसीआई को लिखे पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए दिए गए कम समय, यानी 24 घंटे, पर आश्चर्य व्यक्त करना चाहते हैं।

पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक और झटका लगा। कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया ने दिया, जिन्होंने इस मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह घटनाक्रम कांग्रेस नेता की ट्रांज़िट ज़मानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। भाजपा ने कहा कि इस फैसले से सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ खेड़ा के बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियान की पोल खुल गई है। शहज़ाद पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो में कहा था, वे दस्तावेज़ (जिनका इस्तेमाल खेड़ा ने किया था) जाली, नकली, फोटोशॉप्ड और एआई-जनरेटेड निकले; और महज़ आधे घंटे के अंदर ही पूरी सच्चाई सामने आ गई।

नरवणे के खुलासे से राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश?

नईदिल्ली। भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन के हाथों क्षेत्रीय नुकसान की बात को सिरे से खारिज कर दिया। फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से कुछ अंश उद्धृत करने का प्रयास किया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नरवणे ने कहा है कि चीन को एक इंच भी जमीन नहीं दी गई। राहुल ने भ्रम फैलाया, लेकिन अब नरवणे ने अपनी चुप्पी तोड़कर राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। जनरल नरवणे का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध के दौरान सेना को राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। जनरल नरवणे ने खुलकर बोलते हुए कहा कि अप्रकाशित दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मुझे और सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटना पूरी तरह से अनुचित है।

बिहार विधानसभा में तेजस्वी का एनडीए सरकार पर तीखा तंज

पटना। आरजेडी नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मौजूदा राजनीतिक स्थिति के कारणों पर सवाल उठाए। विशेष सत्र में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उन्होंने तर्क दिया कि अगर पार्टी ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए होते तो बहुमत साबित करने के लिए एक दिवसीय सत्र बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तेजस्वी ने कहा कि अगर भाजपा ने पहले ही कह दिया होता कि उसका मुख्यमंत्री पदभार संभालेगा, तो आज की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए नारों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को दर्शाया था। जेडीयू के चुनावी नारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने '2025 से 30, फिर से नीतीश' जैसे नारे देखे।

चुनाव में रिकार्ड मतदान लोकतंत्र के लिए अच्छा : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल (पहले चरण) और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं का मतदान करना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि मतदाताओं की इतनी बड़ी भागीदारी से लोकतंत्र में लोगों की गहरी आस्था का पता चलता है, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने मतदाताओं के आने-जाने की सुविधा के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि एक तरह की लहर चली, और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ। एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) भी एक वजह है जिसके चलते लोगों ने मतदान किया। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत होता है।

दमदम में दिखा प्रधानमंत्री का दमखम

बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है टीएमसी का दीया : मोदी

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महा जंगल राज के अंत की शुरुआत बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनेगी। उन्होंने महिला मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया और टीएमसी को महिला-विरोधी पार्टी बताया। दम दम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का हौसला पस्त हो गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव हारने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़ें, और साथ ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भगवा पार्टी ने रत्ना देबनाथ को टिकट दिया है, जो आरजी कर रेप-मर्डर केस की पीड़िता की माँ हैं।

गुरुवार को बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन देखने को मिला, उसने उसकी जीत का बिगुल बजा दिया है। पश्चिम बंगाल में, जहाँ टीएमसी ने अपने तानाशाही रवैये से लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था और उसे कमज़ोर कर दिया था, वहाँ की जनता ने पहले ही चरण में उस लोकतंत्र के मंदिर को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा बंगाल की हर बहन-बेटी के सपनों को पूरा करने और उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की बहनों से भाजपा का सीधा वादा है कि भाजपा आपको सुरक्षा देगी, भाजपा आपको सम्मान देगी और भाजपा से ही आपको समृद्धि मिलने वाली है। भाजपा सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशहाली आएगी, गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा। कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा। आपका घर का सपना भी पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी और जो घर बनेगा

वो महिलाओं के नाम पर ही होगा। मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं कि भाजपा, बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। 4 मई को भाजपा सरकार बनने के बाद हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइल खुलेगी। ये मोदी की गारंटी है।

ये सुशासन के नए युग की शुरुआत है : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में रिकॉर्ड-तोड़ मतदान के लिए मतदाताओं को बधाई दी। भाजपा की जीत की ओर इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि मतदाताओं की भारी भागीदारी और शांतिपूर्ण मतदान, पश्चिम बंगाल में सुशासन के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाह ने लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के सम्मानित मतदाताओं को लोकतंत्र के इस भव्य उत्सव में, मतदान के पहले चरण में ऐतिहासिक भागीदारी के माध्यम से सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। पोस्ट में आगे कहा गया कि मैं माननीय चुनाव आयोग, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बहादुर जवानों और हमारी पश्चिम बंगाल पुलिस का बंगाल के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान प्रक्रियाओं में से एक को सुनिश्चित करने के लिए गहरा आभार और बधाई व्यक्त करता हूँ। यह बंगाल में सुशासन के एक नए युग की शुरुआत का स्पष्ट संकेत है।

पश्चिम बंगाल में विदा होंगी दीदी

भाजपा पहले चरण में 110 से ज़्यादा सीटें जीतेगी : शाह

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। शाह के अनुसार, पहले चरण में हुई 92.88 प्रतिशत की ऐतिहासिक वोटिंग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य की जनता ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार को राज्य में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमें जो फीडबैक मिला है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता ने पहले चरण में ही अपना फ़ैसला कर लिया है। 16 ज़िलों की 52 सीटों पर 92.98 प्रतिशत वोटिंग यह दिखाती है कि दीदी की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। डर खत्म होगा और उसकी जगह भरोसा लेगा।

उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि भाजपा राज्य में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 110 से ज़्यादा सीटें जीतने की राह पर है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, गुरुवार रात कमेटी के सदस्यों के साथ हालात का जायज़ा लेने के बाद, हमारा

अनुमान है कि भाजपा 152 सीटों में से 110 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसका मतलब है कि वोटिंग के दूसरे चरण के बाद, हम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने की राह पर हैं।

उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं चुनाव आयोग, सीएपीएफ और बंगाल पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय बाद यह पहला चुनाव था जिसमें किसी एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। पहले चरण के बाद यह साफ़ है कि बंगाल के मतदाताओं ने विकास को चुना है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की यात्रा अब बंगाल पहुंचेगी और लोग इसमें शामिल होंगे।

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री यह अफ़वाह फैला रही हैं कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है, तो बाहरी लोग राज करेंगे।

केरल में नतीजों से पहले कांग्रेस में घमासान

सीएम के चेहरे की लड़ाई से यूडीएफ की बढ़ी मुश्किलें

तिरुवनंतपुरम। केरल में चुनाव नतीजों से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है, लेकिन इस बार मुकाबला केवल विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई अंदरूनी खींचतान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

राज्य में 9 अप्रैल को मतदान हो चुका है और अब 4 मई को नतीजों का इंतजार है। करीब 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए यूडीएफ खेमे में उत्साह तो है, लेकिन इसी बीच नेतृत्व को लेकर उठी बहस ने माहौल असहज कर दिया है।

केरल की राजनीति में लंबे समय तक हर चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने दोबारा सरकार बनाकर इस परंपरा को तोड़ दिया था। ऐसे में इस बार का चुनाव कांग्रेस और यूडीएफ के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

इसी बीच कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खुलकर दावेदारी सामने आने लगी है। वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला, विपक्ष के नेता वी डी सतीशान और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल के समर्थक सार्वजनिक रूप से अपने-अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं।

यह बहस चुनाव परिणाम आने से पहले ही शुरू हो जाने से पार्टी नेतृत्व असहज स्थिति में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की खुली बयानबाजी से मतदाताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। वरिष्ठ मीडिया आलोचक एम एन करासेरी ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि सत्ता मिलने से पहले पद की लड़ाई जनता का भरोसा कमजोर कर सकती है।

इस विवाद का असर सहयोगी दलों पर भी पड़ने लगा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता और विधायक पी अब्दुल हमीद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर इस तरह की चर्चा सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इससे यूडीएफ समर्थकों और जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है, जो लंबे समय से विपक्ष में रहकर संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन नेताओं को इस बहस को रोकना चाहिए था, वही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा, सभी उसे मानेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और अंतिम फैसला सोच-समझकर लिया जाएगा।

दूसरी ओर, वाम दलों ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। इसके उलट कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आने से कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में चुनाव नतीजों से पहले यूडीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि घर के भीतर की लड़ाई बनती दिख रही है।

खेल
प्रमुख समाचार

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत आज

नईदिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अपने अभियान को फिर से पटरी पर लाने के लिए शनिवार को होने वाले मुकाबले में तालिका में शीर्ष पर चल रही पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 47 रन से हार का सामना करने वाली दिल्ली के लिए वापसी की राह काफी चुनौतीपूर्ण होगी। इसके लिए उसके ज्यादातर खिलाड़ियों को एक साथ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। छह मैचों में तीन जीत और तीन हार के साथ दिल्ली फिलहाल अंकतालिका के छठे स्थान पर है, जबकि पंजाब किंग्स छह मुकाबलों में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। उनका एकमात्र अंक तब गया था जब कोलकाता में मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या उसकी बल्लेबाजी में अस्थिरता रही है। केएल राहुल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने कुछ पारियों में योगदान दिया है, लेकिन पूरी टीम एक साथ प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में असफल रहे हैं, जिससे मध्यक्रम पर दबाव बढ़ गया है। कप्तान अक्षर पटेल से भी उम्मीद की जा रही है कि वह बल्ले और रणनीति दोनों में अधिक जिम्मेदारी निभाएं।

पिछले मैच में उनके कुछ निर्णयों पर भी सवाल उठे हैं, खासकर गेंदबाजी बदलावों को लेकर। विस्फोटक अभिषेक शर्मा के खिलाफ उन्होंने कामचलाऊ गेंदबाज नितीश राणा को लगातार इस्तेमाल किया, जो असरदार साबित नहीं हुआ। दिल्ली का क्षेत्ररक्षण भी चिंता का विषय रहा है। टीम ने कुछ मैचों में स्टंपिंग के मौके गंवाए, रन-आउट में गलतियां कीं और आसान कैच छोड़े, जिसका उसे काफी नुकसान हुआ है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 982 अंक टूटा निफ्टी 23897 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के अंतिम ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार (24 अप्रैल) को बड़ी गिरावट में बंद हुए। अमेरिका-ईरान वार्ता में ठहराव और होरमुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी के चलते तेल की कीमतों में तेजी आई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 150 से ज्यादा अंक गिरकर 77,483.80 पर खुला। जबकि गुरुवार को यह 77,664.00 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 76,403 अंक तक गिर गया था। अंत में 982.71 अंक या 1.27 प्रतिशत की गिरावट लेकर 76,681.29 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 24,100 पर खुला। खुलने के कुछ ही देर में यह 24 हजार के नीचे फिसल गया। कारोबार के दौरान यह 23,813 अंक तक लुढ़क गया था। अंत में यह 275.10 अंक या 1.14 फीसदी की गिरावट लेकर 23,897 पर बंद हुआ।

कच्चे तेल की 'आग' से तेल कंपनियां झुलसीं

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव का असर अब भारतीय तेल कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण देश की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी घाटा उठा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कंपनियों को डीजल पर करीब 100 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर लगभग 20 रुपए प्रति लीटर का नुकसान (अंडर-रिकवरी) हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियों ने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, कच्चे तेल की औसत कीमत पिछले साल के 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर इस महीने 113 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर तेल कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा है।

गौतम अडानी की 100 अरब डॉलर क्लब में हुई एंट्री

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अडानी अब 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं। नेटवर्थ के मामले में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, गुरुवार को नेटवर्थ में 7.16 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 106 अरब डॉलर हो गई। अडानी अब दुनिया के अमीरों की सूची में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बिल गेट्स की नेटवर्थ घटकर 104 अरब डॉलर रह गई है और वे 18वें स्थान पर आ गए हैं। साल 2026 में अब तक अडानी की संपत्ति में 21.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि बिल गेट्स की नेटवर्थ में इसी अवधि में 12.7 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकवाली के दबाव के चलते दोनों कीमती धातुओं के दाम करीब आधा प्रतिशत तक फिसल गए। सोने की कीमतें 462 रुपये गिरकर 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, जून डिलीवरी के लिए पीले धातु की कीमत 462 रुपये या 0.3 प्रतिशत गिरकर 1,51,299 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 8,310 लॉट का कारोबार हुआ। वहीं चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखी गई। 5 मई 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट पिछले बंद 2,41,513 रुपये के मुकाबले 2,39,200 रुपये पर खुला। सुबह के कारोबार में यह 842 रुपये यानी 0.35 प्रतिशत टूटकर 2,40,671 रुपये पर पहुंच गया।

हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की ताकत

डॉ भूषण दीवान

पिछले दिनों भारत ने समुद्री क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। देश की प्रमुख रक्षा शिपबिल्डिंग कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। भारत ने पहली बार किसी विदेशी शिपयार्ड का अधिग्रहण किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन देश की प्रमुख डिफेंस शिपबिल्डिंग कंपनी एमडीएल ने श्रीलंका में परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है और कोलंबो डॉकयार्ड अब उसकी सहायक कंपनी बन गया है।

यह सुविधा कोलंबो बंदरगाह के अंदर स्थित है, जहां चार ग्रेविंग डॉक हैं-सबसे बड़ा 1,25,000 डेडवेट टन (डीडब्ल्यूटी) क्षमता वाला। विस्तृत रिपेयर बर्थ सुविधाएं भी वहां उपलब्ध हैं। वर्ष 1974 से संचालित यह शिपयार्ड जहाज निर्माण, मरम्मत, भारी इंजीनियरिंग व ऑफशोर कार्यों में श्रीलंका का अग्रणी केंद्र है। यह कदम भारत की समुद्री नीति के लिए मील का पत्थर और देश की समुद्री महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह सिर्फ एक कंपनी का वाणिज्यिक सौदा नहीं है, 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) नीति का व्यावहारिक रूप है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, 2047 के सपने को समुद्री क्षेत्र में ले जाता है।

अभी तक भारत जहाज निर्माण में आयात पर निर्भर था, पर अब विदेशी शिपयार्ड के जरिये उसके लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन और प्रशिक्षण का द्वार खुल गया है। यह कदम आर्थिक लाभ के साथ-साथ श्रीलंका के साथ रिश्तों में कूटनीतिक भरोसा बढ़ाने वाला भी है।

श्रीलंका को जहां एक वैकल्पिक साझेदार मिल रहा है, वहीं भारत अपनी समुद्री उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह भारत की सक्रिय समुद्री कूटनीति का उदाहरण है, जो 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति को मजबूत बनाता है। कोलंबो डॉकयार्ड पर नियंत्रण हासिल करने को हंबनटोटा का रणनीतिक जवाब माना जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से उसका जवाब कहना ठीक नहीं। वर्ष 2017 में कर्ज चुका पाने की असमर्थता के कारण श्रीलंका ने हंबनटोटा बंदरगाह का पट्टा 99 साल के लिए चीन को दे दिया था, और चीन की मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स ने उसे 'डेट-ट्रैप डिप्लोमेसी' का प्रतीक बना दिया। हंबनटोटा अब चीनी नौसैनिक जहाजों के लिए रसद और संभावित निगरानी केंद्र बन सकता है, जो भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है। जबकि कोलंबो डॉकयार्ड का भारत द्वारा अधिग्रहण रिश्तों में संतुलन बहाली का कदम है।

हिंद महासागर के मुख्य समुद्री मार्ग पर स्थित कोलंबो बंदरगाह दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्त हब है। भारत इस पर जहाज मरम्मत और निर्माण की क्षमता हासिल कर रहा है। हमारा यह कदम चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति को चुनौती देता है, लेकिन सकारात्मक तरीके से। ऋण जाल में फंसाने के बजाय श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता सहयोग और निवेश के आधार पर है। श्रीलंका भी इस सौदे से लाभान्वित होगा, क्योंकि जापान के ओनोमिची डॉकयार्ड से शेयर खरीदकर भारत ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी है। भारत का यह कदम 'आक्रामक' नहीं, संतुलित और सहयोगी है। क्षेत्रीय, आर्थिक और रक्षा दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत की समुद्री क्षमता में गुणात्मक वृद्धि होगी। कोलंबो डॉकयार्ड की क्षमता भारत को बड़े जहाजों की मरम्मत और निर्माण का क्षेत्रीय केंद्र बनायेगी। मेरीटाइम अमृत काल विजन, 2047 के तहत भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पांच शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होना चाहता है।

यह सौदा उस लक्ष्य की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। आर्थिक रूप से यह कदम रोजगार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात बढ़ायेगा। रक्षा दृष्टि से एमडीएल अब विदेशी युद्धपोतों, पनडुब्बियों और सहायक जहाजों की मरम्मत कर सकेगा। भू-राजनीतिक दृष्टि से यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता बढ़ायेगा।

मुख्यमंत्री पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में हुए शामिल

पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का विकास होगा: सीएम साय

रायपुर। डबल इंजन की हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गांवों के समग्र विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का विकास होगा और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत प्रतिनिधि के रूप में की थी तथा पंच और सरपंच के दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास को लेकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वही आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आज हजारों जनप्रतिनिधि पंचायत से अपना सफर शुरू कर देश के उच्च सदनों तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने से ही प्रभावी नीतियां बनती हैं।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं अब ग्रामीणों के

लिए सहज हो गई हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। महिलाओं के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं और इनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है।मुख्यमंत्री साय ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायतों में संचालित सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सभी विकास कार्य पूर्ण हो सकें। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की जिम्मेदारी बड़ी है और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने में पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार के आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सुशासन तिहार के आयोजन और इसके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें सरचार्ज पूरी तरह माफ किया गया है और अतिरिक्त रियायत का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी और सभी प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की अपील की। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट छांव के अंतर्गत आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर और विभिन्न प्रोजेक्ट पर आधारित स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं से चर्चा की और आजीविका संवर्धन के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन रायपुर द्वारा नवजात शिशुओं में जन्मजात हृदय रोगों की पहचान के लिए प्रोजेक्ट धड़कन, देहदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट दधीचि, किसानों को नवाचार से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट नैनो, प्रोजेक्ट रचना, प्रोजेक्ट स्मृति पुस्तकालय, प्रोजेक्ट पाई-पाई, ग्लोबल गांव, ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट सिग्नल, मेरा गांव मेरी पहचान, प्रोजेक्ट अजा, प्रोजेक्ट बिजनेस दीदी समेत विभिन्न प्रोजेक्ट के स्टालों का अवलोकन किया और हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र एवं राशि का वितरण किया।

भीषण गर्मी में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए त्वरित एवं संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार 30 जून 2026 तक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रात: 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस अवधि में बच्चों की उपस्थिति केवल सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक निर्धारित की गई है, ताकि उन्हें अत्यधिक तापमान एवं लू के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा गतिविधियाँ निर्धारित समय-सारिणी एवं कलेण्डर के अनुसार संचालित होंगी तथा पूरक पोषण आहार का वितरण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे बच्चों के

पोषण एवं शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए। निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र प्रात: 7:00 बजे से प्रारंभ होंगे, जिसमें बच्चों की उपस्थिति 7:00 से 9:00 बजे तक रहेगी, जबकि अन्य सेवाओं के लिए केंद्र 11:00 बजे तक संचालित रहेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने जॉब चार्ट के अनुसार शेष कार्यों का निष्पादन करेंगी।मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श सेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र बंद होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घर-घर जाकर माताओं को जागरूक करेंगी। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्म हवाओं, अधिक तापमान एवं लू की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।हिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करें तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें, ताकि जमीनी स्तर पर निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल समाप्ति उपरांत 01 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी केंद्र पुन: अपने सामान्य समय प्रात: 9:30 बजे से 3:30 बजे तक (6 घंटे) संचालित किए जाएंगे।

रायपुर में पीएम सूर्य घर योजना की साप्ताहिक समीक्षा

रायपुर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस कक्ष में ली। बैठक के दौरान सीईओ कुमार बिश्वरंजन ने योजना की वर्तमान प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी अनावश्यक बाधा के समय पर योजना का लाभ मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही यदि किसी आवेदन को निरस्त किया जाता है, तो संबंधित आवेदक को अस्वीकृति का स्पष्ट कारण अनिवार्य रूप से बताने को कहा गया। सीईओ ने बैंक, सीएसपीडीसीएल और वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल जरूरी है।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल की मौजूदगी में डीएमएफ शासी परिषद की बैठक

रायपुर। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि डीएमएफ निधि का अधिकतम उपयोग जनहित के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और स्वच्छता में किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो। साथ ही उन्होंने सुपर 30 कोचिंग योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने पर विशेष जोर दिया।मंत्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति तथा कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास अजीत वसंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट अंबिकापुर सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और कहा कि

सभी विभाग अपने प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर तैयार करें, ताकि डीएमएफ राशि का प्रभावी और जनहितकारी उपयोग सुनिश्चित हो सके।कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि नए नियमों के अनुरूप पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने हेतु विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि डीएमएफ निधि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार करते हुए जिले के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव डीएमएफ विनय अग्रवाल ने वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक विभिन्न सेक्टरों में स्वीकृत, पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल कल्याण तथा स्वच्छता से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डीएमएफ अंतर्गत ऑडिट कार्य के अनुमोदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से जिले के विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

साय सरकार में प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जांजगीर-चांपा के जैजेपुर में एक व्यवसायी के घर में घुस कर गोली मारे जाने की घटना बेहद ही चिंता का विषय है। यह घटना राज्य की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। जांजगीर-चांपा में व्यवसायी के घर में आपराधियों ने उनके बड़े बेटे की गोली मार कर

हत्या कर दिया, छोटा बेटा घायल है। अब आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो चुके कि उनमें कानून का जरा भी भय नहीं बचा है। जांजगीर की घटना के पहले प्रदेश में गैंगवार की अनेकों घटनाएं पिछले ढाई साल में हुई है। राजधानी में पांच बार गोलियां चलाई गई, रायपुर सेंट्रल जेल के सामने गोलियां चलाई गई, झारखंड के गैंगस्टर रायपुर में गोलीबारी कर चुके है, बिलासपुर के मस्तूरी में व्यवसायी के ऊपर गोलियां चलाई गयी। अब तो घर में घुस कर गोली मारी जा रही है। अपराधी घर में घुस कर गोली मार रहे, गृह मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाओं के आंकड़े बताते है कि राज्य की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है।

अघोषित बिजली कटौती से आम जनता परेशान: शुक्ला

रायपुर। गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली की कटौती आम आदमी के लिये सरदर्द बन गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। ढाई साल में विद्युत सरप्लस वाला

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटो बिजली गोल हो जाती है। भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थायें। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में तो पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। भाजपा सरकार में आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी किया जाता था।

एकमुश्त चांवल भी निकला जुमला: ठाकुर

रायपुर। वन नेशन वन राशन कार्ड को जुमला ठहराते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार से पूछा वन नेशन, वन राशन कार्ड से हितग्राहियों को तीन माह का चांवल क्यों नहीं दिया जा रहा है? राशन दुकान वाले उन्हें वापस क्यों लौटा रहे है? कई राशन दुकानों में एकमुश्त तीन माह का राशन की जगह

एक माह का चांवल दिया जा रहा, हितग्राहियों को चांवल नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में हितग्राहियों को स्टॉक खत्म होने के चलते चांवल नही मिल रहा है, आखिर सरकार तीन माह की एकमुश्त राशन देने की घोषणा के साथ पर्याप्त मात्रा में चांवल की उपलब्धता राशन दुकानों में क्यों नहीं की है? राशन दुकान में चांवल ही नहीं रहेगा तो दुकानदार कहां से देंगे? खराब क्वालिटी की चांवल मिलने की शिकायत आ रही है? ये तो गरीब जनता के साथ भद्दा मजाक है, गरीब जनता का अपमान है?प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 30 लाख राशन कार्ड धारियों को केवायसी के कारण तीन माह का राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करे जिनका केवायसी नहीं हुआ है उनको भी चांवल दिया जाये। केवायसी में तकनीकी दिक्कत आ रही है।

महिला आरक्षण को लेकर भाजपा बेनकाब हो गयी: वंदना

रायपुर। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा बेनकाब हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि संसद में भाजपा ने परिसीमन विधेयक पास कराने के लिये महिला आरक्षण बिल का सहारा लिया, लेकिन विपक्षी दलों और कांग्रेस पार्टी की जागरूकता से भाजपा बेनकाब हो गयी और उसकी चाल सफल नहीं हुई। भाजपा

महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, वह अपनी चुनावी गणित के हिसाब से परिसीमन कराना चाह रही, उसमें वे सफल नहीं हो पाया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 131 वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। संसद में जो विधेयक गिरा उसमें इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था राज्यों में 815 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें। परिसीमन विधेयक- जिसमें परिसीमन के लिये 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की गयी थी। विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन की बात की गयी थी।

गुजरात में बढ़ते जनाधार से घबराई भाजपा: उत्तम

रायपुर।आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से घबराकर साजिश रच रहे हैं। उत्तम जायसवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और मजबूत संगठन खड़ा कर चुके हैं। यही कारण है कि भाजपा में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब,क्क को तोड़ने और उसके नेताओं को भटकाने की कोशिशों में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक मित्तल पर 15 अप्रैल को श्वष्ठ की रेड होती है और आज अशोक मित्तल भाजपा ज्वाइन कर लेतें हैं? ये दर्शाता है कि अमित शाह विपक्ष के नेताओं को डरा धमकाकर भाजपा के लिए ऑपरेशन लोटस चला रहें हैं और देश में लोकतंत्र खत्म कर रहें हैं! उन्होंने राज्यसभा सांसद के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, राज्यसभा तक पहुंचाया, उसी पार्टी के साथ विश्वासघात करना न सिर्फ राजनीतिक बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। जायसवाल ने आगे कहा कि संबंधित सांसद ने पंजाब की जनता के साथ भी बड़ा धोखा किया है और भाजपा के साथ मिलीभगत कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात का प्रमाण है।

वित्त मंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया

रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने गुरुवार संध्या अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरमेकला ब्लॉक में व्यापक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान लगभग 1 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 9 लाख रुपये की लागत वाले नए कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया। वित्त मंत्री ने गोबरसिंहा, साल्हेओना मानिकपुर बड़े, विश्वासपुर और बरगांव सहित कई गांवों में पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा-अर्चना के

साथ की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों और किसानों में उत्साह देखने को मिला।

किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उन्हें सरसों तथा केले से तौला गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, उपाध्यक्ष अजय नायक, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल, डॉ. अभिलाषा नायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। लोकार्पण किए गए प्रमुख विकास कार्यों में गोबरसिंहा में सीसी रोड निर्माण (फुरसो घर से लक्ष्मीनारायण घर तक) 10 लाख रुपये, बाजार परिसर में नाली निर्माण 10 लाख रुपये, सीसी रोड निर्माण 13 लाख रुपये तथा सड़क मरम्मत कार्य 5 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत कटंगी नाला में 14.46 लाख रुपये की लागत से चेक डैम निर्माण कार्य भी शामिल है।

साल्हेओना में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र (सीएससी भवन) निर्माण के लिए 5 लाख रुपये और शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया गया। विश्वासपुर में सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपये तथा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये के कार्य शामिल हैं। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है और जनता की जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और जब तक जीवन है, क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे।

उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वे लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा पा रहे हैं।

न्यू एज मीडिया में दक्ष बनें जनसंपर्क अधिकारी : आयुक्त रजत बंसल

रायपुर। जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने आज नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में जनसंपर्क संचालनालय और जिला जनसंपर्क अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि वर्तमान दौर में जनसंपर्क अधिकारियों को न्यू एज मीडिया की सभी विधाओं में दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ तकनीक और संचार के नए माध्यमों को अपनाना ही प्रभावी जनसंपर्क की कुंजी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसंपर्क का कार्य अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोताही से बचना जरूरी है। जनसंपर्क अधिकारी शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि परिणाम के अनुरूप हर अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि मंत्रिगणों, विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिले के कलेक्टरों के साथ नियमित संपर्क और समन्वय बनाएं। इससे सूचनाओं का समयबद्ध और प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा, जो शासन की योजनाओं के सही क्रियान्वयन और प्रचार के लिए अत्यंत आवश्यक है।जनसंपर्क आयुक्त ने आगामी एक मई से शुरू हो रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.